सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivahan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 27, नई दिल्ली | बुधवार, 12 अप्रैल 2023, मूल्य ` 5, पेज 8

आज का सुविचार

"सफलता की ख़ुशी मनाना अच्छा है पर, उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना !

वाहन को स्क्रैप करवाने में परिवहन विभाग का एप करेगा मदद, चल रही है तैयारी

संजय बाटला

नईदिल्ली। अगर 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पेट्रोल वाहन के पूरे हो चुके हैं तो आप इसे स्क्रैप करने के लिए खुद घोषित कर सकेंगे। इससे न तो वाहनों के जब्त होने का खतरा रहेगा और न ही मियाद पूरी होने वाले वाहनों को स्क्रैप करने की चिंता सताएगी।

अगर आपके वाहन को स्क्रैप कर दिया गया है तो भी जानकारी परिवहन विभाग को दे सकेंगे। वाहनों का सर्वे करने के लिए परिवहन विभाग एप विकसित करेगा। यह आधार से जुड़ा होगा और एक क्लिक पर वाहनों का पूरा ब्योरा उपलब्ध करा देगा। वाहन को स्क्रैप करवाने में यह एप काम करेगा।

परिवहन विभाग की तरफ से पुराने वाहन मालिकों को राहत देने के लिए वॉलेंटरी डिसक्लोजर ऑफ स्क्रैप (वीडीएस) की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे तमाम वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से आय की स्वैच्छिक घोषणा (वीडीआईएस) की तर्ज पर स्क्रैप की जानकारी भी साझा कर सकेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए वाहनों को स्क्रैप करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वीडीएस की दिशा में पहल का वाहन मालिकों के साथ-साथ विभाग को भी फायदा मिलेगा।

इससे न तो वाहनों के जब्त होने का खतरा रहेगा और न ही मियाद पूरी होने वाले वाहनों को स्क्रैप करने की चिंता सताएगी।

आधार बताएगा आपके वाहन का पूरा ब्योरा

वीडीएस के तहत अपना मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी जारी होगा। इसके बाद आधार कार्ड का ब्योरा देने पर वाहन की पूरी जानकारी सामने होगी। अगर वाहन को स्क्रैप कर दिया गया तो इसकी स्वैच्छिक घोषणा कर सकेंगे। अगर मियाद पूरी होने के बाद वाहन को स्क्रैप करवाना है तो भी इस एप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

सुरक्षा की नहीं सताएगी चिंता : वाहनों को स्क्रैप करने पर जारी होने वाले सर्टिफिकेट से नए वाहनों की खरीद पर रियायत का प्रावधान है। सुरक्षा के लिहाज से भी यह बेहद जरूरी है। इसके लिए वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के बाद स्क्रैप किया जाता है। निजी वाहनों को स्क्रैप करने के बाद सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं। ऐसे में वाहनों का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बना रहता है।

यार्ड में वाहनों को किया जा रहा स्क्रैप

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का सिलसिला कई वर्ष से चल रहा है। अभी तक निजी स्क्रैप कारोबारियों से वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा था। उनसे स्क्रैप के बदले राशि अधिक मिलती रही, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अधिकृत एजेंसियों से ही वाहनों को स्क्रैप करवाने की जानकारों की सलाह है। इसके लिए सरकार ने आठ एजेंसियों को अधिकृत किया। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी रूल्स (आरवीएसएफ)-2021 के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के शहरों में स्क्रैप यार्ड के लिए लाइसेंस लिए गए हैं। कार्रवाई के तहत जब्त होने वाले वाहनों को अधिकृत एजेंसियों में स्क्रैप कर दिया जाता है। फिलहाल एमसीडी के 12 जोन से निकलने वाले वाहनों को एजेंसियां स्क्रैप कर रही हैं।

जरूरत नहीं है तो बेच भी सकते हैं सीओडी : अधिकृत एजेंसियों में वाहनों को स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी किया जाता है। इसे नए वाहनों को खरीदने पर रोड टैक्स पर छूट सहित दूसरी रियायतें मिल सकती हैं। अगर आपके पास इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है तो इसे बेच भी सकते हैं। इससे नए वाहन खरीदने वालों को भी राहत मिल सकती है।

ई-वाहनों में दोपहिया की 47% हिस्सेदारी

दिल्ली में ई-वाहनों की खरीदारी में दोपहिया सर्वाधिक हिस्सेदारी रही है। जनवरी से मार्च के दौरान 18175 ई- वाहनों की बिक्री हुई। इनमें 47 फीसदी दोपहिया, जबकि 33 फीसदी तिपहिया वाहन हैं। इनमें ई-ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक ई-वाहन भी शामिल हैं। इस दौरान ई-कारों की 19 फीसदी हिस्सेदारी रही।

साल 2020 से इस साल पहली तिमाही तक एक लाख से अधिक ई-वाहनो का दिल्ली में पंजीकरण हुआ है। 2020 में कुल 25808, 2021 में 62241, जबकि 2022 में 18765 ई-वाहनों की बिक्री हुई है। साल की पहली तिमाही में 18 हजार ई-वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पिछले साल की कुल बिक्री से थोड़ा कम है।

ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में !!!
निर्भकता से आपके लिए प्रस्तुत करे खबरे
सिर्फ और सिर्फ, सच :- परिवहन विशेष

अब आपके लिए अवसर परिवहन विशेष समाचार पत्र मे काम करने का

अगर आप को पत्रकारिता का शौक है और जनहित के मुद्दों को लिखने/उठाने और उनका हल करवाने के इच्छुक है तो आप परिवहन विशेष (हिन्दी दैनिक) समाचार पत्र के साथ जुड़कर अपना सपना/इच्छा पूरी कर सकते हैं।

इस फेलोशिप के जरिए आपको मिलेगा पत्रकारिता में सफलता प्राप्त कर पत्रकार बनने के अवसर । फेलोशिप के दौरान आप देश के हिन्दी अखबार दैनिक के साथ काम कर पाएंगे। 15 माह की फेलोशिप पूरी करने के बाद आपके पास होगा परिवहन विशेष में नौकरी करने का अवसर ।

जर्नलिजम प्रिंट एवं डिजिटल फेलोशिप

फेलोशिप के दौरान दूसरे माह से कार्य करने के प्रति जागरूकता और क्षमता के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

जरूरी योग्यता :-हिन्दी बोलने, पढ़ने और लिखने में दक्षता।

आवेदन 25 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 के बीच किए जा सकते हैं।

newstransportvishesh@gmail.com
www.newstransportvishesh.com

DELHI TAXI, TOURIST TRANSPORTERS & TOUR OPERATORS ASSOCIATION (Regd.)
Regd. Off. : F-16, Ist Floor, Saidulajaab, Near Saket Metro Station, New Delhi-110030
Ph. : 011-40518321 | M : 9717906644, 9958068373, 9810182147 | Fax : 011-40518321,
Email : delhitaxi2003@gmail.com

Ref. : .... Date : 11-04-2023

सेवा में,
श्री ज्ञानेश भारती जी,(IAS)
कमिश्नर , दिल्ली नगर निगम
सिविक सेंटर, मिंटो रोड नई दिल्ली.

विषय :- MCD टोल टैक्स में RFID टैग के बहाने परेशान करने और करोडो रुपए के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत.

आदरणीय कमिश्नर साहब, हम दिल्ली एनसीआर के टूरिस्ट टैक्सी-बस और टेम्पो ट्रेवलर वाले MCD टोल टैक्स, RFID टैग द्वारा लेने से बड़े परेशान हैं और इस RFID टैग के बहाने करोडो रुपए का भरस्टाचार हो रहा है. मैं आपके संज्ञान में कुछ बाते लाना चाहता हूँ.

1. दिल्ली में एंट्री करने के 126 पॉइंट(बॉर्डर)हैं जिसमे RFID टैग को स्कैन करने के कुछ ही पॉइंट्स (बॉर्डर) पर स्कैनर लगे हैं.

2. जहाँ स्कैनर लगे हैं वो भी काफी जगह काम नहीं कर रहें हैं जिसकी वजह से हर गाडी को दिल्ली के बॉर्डर पर 10 से 20 मिनट तक लग रहें हैं जिस से दिल्ली बॉर्डर पर काफी लम्बा जाम लग रहा हैं और प्रदुषण भी हो रहा हैं.

3. काफी बार RFID टैग का पैसे ट्रांसफर करने का लिंक ही काम नहीं कर रहा हैं और काफी बार गाडी मालिक जब RFID टैग के वॉलेट में पैसा जमा करवा रहें हैं तो वो पैसा उनके अकाउंट से जमा हो रहा हैं लेकिन RFID वॉलेट में समय से नहीं पहुँच रहा हैं. जिसकी वजह से दिल्ली बॉर्डर पर MCD टोल नाके पर खड़ा स्टाफ हमारे गाडी वालो से दोगुना पैसा वसूल रहा हैं और उसकी कोई रसीद भी नहीं दे रहा हैं.

4. अगर किसी को RFID टैग अपनी गाडियों में लगाना हो तो वो भी हमें नहीं मिल रहा हैं.

आदरणीय कमिश्नर साहब, RFID टैग 250 रुपए में दिया जा रहा हैं जबकि इसकी कीमत 5 रुपए भी नहीं होंगी अरबो रुपए पूरे भारत के गाडी वालो से लिए जा रहें हैं जो कमर्सयल गाड़ियाँ दिल्ली में आ रहीं हैं, फिर RFID वॉलेट में लाखों गाडी वालो से अरबो रुपए जमा करवाये जाते हैं उनमे से हजारों गाड़ियाँ बिक जाती हैं या दुर्घटना होकर कबाड़ बन जाती हैं,आज तक काफी सालो से किसी भी गाडी वालो को वो पैसा वापिस नहीं मिला. ये पैसा कहाँ गया? इसकी जांच जरूरी हैं, क्योंकि इसमें करोडो रुपए के भ्रष्टाचार की संभावना हमें लग रहीं हैं.. आप से विनती हैं की जो पैसा RFID वॉलेट में रह गया हैं किसी भी गाड़ी वाले का वो पैसा गाडी वालो को जरूर मिलना चाहिए.

सबसे बड़ी बात RFID टैग को बंद करके MCD टोल टैक्स फास्टेग से लेना चाहिए.

और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सारे बॉर्डर पर सिर्फ नगद पैसा लेकर टोल टैक्स की रसीद दी जाए क्योंकि काफी बार गाडी वालो के एकाउंट्स से भी पैसा कट जाता हैं और MCD टोल कर्मचारी भी नगद पैसा ले लेते हैं, दूसरा आज तक दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर स्कैनर नहीं लगे हैं.

आप से उम्मीद करते हैं की आप हमारी मांगो पर गौर करेंगे .और हमें जल्दी ही मिलने का समय देंगे. धन्यवाद

संजय समाट
अध्यक्ष
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन 9810182147----9717906644

President Sanjay Samrat | General Secretary Hari Singh | Treasure Mohan Singh

MCD टोल टैक्स के बहाने RFID टैग की कमियों और उसमे हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कमिश्नर को लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजय सम्राट ने MCD टोल टैक्स के बहाने RFID टैग की कमियों और उसमे हो रहें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पत्र श्री ज्ञानेश भारती जी, MCD कमिश्नर को लिखा.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हें की सबसे पेहले दिल्ली की पंजीकृत कमर्सयल गाड़ियों से MCD टोल टैक्स लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर साल MCD का सालाना पार्किंग शुल्क देते हें. संजय सम्राट का कहना हें की जब पेहले से ही हमारी गाड़ियों पर फास्टेग लगा हें तो RFID टैग अलग से क्यों?RFID टैग के बहाने इसमें करोडो -अरबो रुपए का भ्रष्टाचार हें क्योंकि एक RFID टैग लगाने के हमसे 250 रुपए लिए जाते हें, जिसकी कीमत 5 रुपए भी नहीं हें, इसके बाद हर गाडी का अलग से वॉलेट अकाउंट बनाना पड़ता हें और उसमे मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता हें. दिल्ली में लाखों कमर्सयल गाड़ियाँ आती हें. आप अंदाजा लगा सकतें हें की एक गाडी के 250 के हिसाब से कितना पैसा बनता हें?

उसके बाद RFID वॉलेट अकाउंट में अरबो रुपए जमा हो जाते हें जिसका ना हमें ब्याज मिलता हें और ना ही कोई अन्य फायदा बल्कि काफी बार RFID वॉलेट अकाउंट में पैसा होने के बावजूद इन कम्पनियो के सर्वर डाउन होते हें या स्कैनर काम नहीं करते, फिर ये हमसे नगद पैसे लेते हें, और काफी बार नगद पैसे देने पर कोई रसीद भी नहीं मिलती और काफी समय बाद RFID वॉलेट अकाउंट से भी पैसे कट जाते हें,संजय सम्राट का कहना हें की काफी टैक्सी - बस वालो ने उन से शिकायत की हें की काफी बार तो RFID वॉलेट का पैसा जमा करने का लिंक ही नहीं खुलता, और अगर गलती से लिंक खुला तो गाडी वालो के अकाउंट से पैसा निकल जाता हें लेकिन काफी समय तक RFID वॉलेट अकाउंट में वो पैसा शो नहीं होता और जब गाडी मालिक दिल्ली बॉर्डर पर आता हें तो MCD टोल टैक्स नाके पर बाऊनसर टाइप के लोग गाडी मालिकों से दोगुना पैसा लेते हें जैसे छोटी गाडी के 100 रुपए की बजाये 200.

संजय सम्राट का कहना की इस वजह से दिल्ली बॉर्डर पर लम्बा जाम लग जाता हें और कमारिसिल गाड़ियाँ 10 से 20 मिनट से ज्यादा बॉर्डर पर खड़ी रहती हें जिस से ट्रैफिक जाम की समस्याओं के अलावा प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ जाती हें, जबकि RFID टैग प्रदूषण को रोकने के लिए ही लगाया गया था.संजय सम्राट का ये भी कहना हें की दिल्ली के अंदर आने के 126 पॉइंट हें जहाँ पर सिर्फ कुछ जगहों पर ही स्कैनर लगे हें और ज्यादार जगह पर अभी भी मैन्युअल काम होता हें.RFID टैग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं हें की अगर RFID टैग के वॉलेट में आप के पैसे जमा हें तो वो वापिस गाडी वालो के अकाउंट में आये.किसी कारण जिन गाडी मालिकों ने अपनी हजारों गाड़ियाँ बेच दी, उनका पैसा आज तक गाडी वालो को नहीं मिला ऐसा ही हजारों गाड़ियों का आगे का शीशा टूट जाता हें या दुर्घटना हो जाती हें उनका भी पैसा इनके RFID वॉलेट अकाउंट में ज़ब्त हो जाता हें संजय सम्राट ने MCD कमिश्नर से मांग की हें RFID टैग में होने वाली समस्याओ का समाधान निकाले और इसमें हो रहें भ्रस्टाचार की भी जांच करें, और जिन गाड़ियों का पैसा RFID वॉलेट में पड़ा हें वो भी वापिस किया जाए साथ ही MCD टोल टैक्स को फास्टेग के साथ जोड़ा जाए और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक MCD टोल टैक्स नगद लेकर उसकी रसीद तुरंत दी जाए.संजय सम्राट का कहना हें की अगर हमारी मांगे जल्दी ही नहीं मानी गईं तो हम MCD कमिश्नर के खिलाफ भारी धरना प्रदर्शन करेंगे।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

IRCTC पैकेज दो दिन में पूरा ट्रिप गोल्डन टेंपल, बाघा बोर्डर, जलियां वाला बाग, टूर शुक्रवार-शनिवार

एसडी सेठी

परिवहन विशेष, नई दिल्ली। हफ्तेभर काम और तनाव से राहत देने की गर्ज से आईआरटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कार्पोरेशन) 2 दिन के पैकेज के तहत सस्ते में अमृतसर घूमने का बढिया मौका दे रहा है। ट्रेंन नई दिल्ली-अमृतसर टूर के तहत वाघा बोर्डर, जलियांवाला बाग,गोल्डन टेम्पल के लिए शुक्रवार-शनिवार दो दिनी के लिए रवाना होगी।

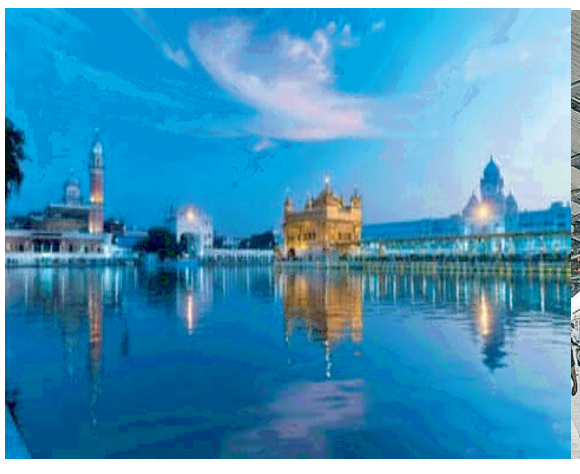

टूर प्लान के तहत- मील प्लान-एपीएआई+एक लंच रहेगा। शुक्रवार पहले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रिपोर्ट करनी होगी। संबंधित यात्रा ट्रेंन नंबर --12029, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस से की जाएगी ।यात्रियों को बोर्ड पर नाश्त मिलेगा। वहीं अमृतसर स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियो को होटल के लिए चेक इन करना होगा। ट्रिप पर यात्रियों को एसी कमरे मिलेगें। फिर लंच के बाद वाघा बोर्डर के लिए प्रस्थान और फिर शाम को होटल में वापसी होगी। इसके बाद रात का खाना और रातभर रहना होगा। दूसरे दिन यानि शनिवार सुबह-सुबह नाश्ते के बाद स्वर्ण मंदिर (गोल्डन टेंपल) दर्शन। इसके बाद जलियांवाला बाग दर्शन के लिए प्रस्थान होगा। लंच के वक्त होटल में वापसी होगी। इसके तुरंत बाद ट्रेंन स्वर्ण शताब्दी नंबर 12030 पर सवार होने के लिए शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर स्थानांतरण एवं बोर्ड पर डिनर दिया जाएगा। इस पैकेज के लिए अलग -अलग कीमत रखी गई है। जिसमें सिंगल शेयरिंग के 8325/_ रूपये, ट्विन शेयरिंग के 6270/- रूपये, ट्रिपल शेयरिंग 5450/-रुपये देने होंगे। वहीं बच्चौ के लिए बेड 4320/- और बिना बेड के 3690/- रूपये चार्ज किए जाएगें। इस बावत पूरी जानकारी रेलवे इंक्वायरी से ली जा सकती है।

दरअसल इन तीनों पार्टीयों का वोट शेयर देशभर में 6 फीसदी से कम हुआ है। अब देश में 6 ही राष्ट्रीय पार्टी बची हुई हैं।

टीएमसी,एनसीपी,सीपीआई को लोकल का दर्जा मिलने से राष्ट्रीय पटल पर बिगड़े

एस.डी सेठी

परिवहन विशेष, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाली कथित राष्ट्रीय पोलिटिकल पार्टी का तमगा पाईं तीन राजनीतिक दलों से उनकी राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छीन लिया है। अब वह क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका में सिमट कर रह गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ये तीनों दल उचित प्रक्रिया का पालन करने और दो संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त अवसर देने के बाद भी राष्ट्रीय पार्टी के उसूलों को बरकरार रखने में कामयाब नहीं रहे हैं। लिहाजा इन पार्टीयों से राष्ट्रीयता का दर्जा खत्म किया जाता है।

इस बावत सोमवार देर शाम को चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिये हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तीरणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल घोषित किये जाने पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जश्न मना रही है। केजरीवाा ने ट्वीट कर कहा कि यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि केजरीवाव ने खलनायक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक का समय दिया था। इसी के मद्देनजर ही आम आदमी पार्टी को ये सर्टिफिकेट मिला है। यह सिंबल आर्डर 1968 के तहत प्रक्रिया है। साल 2019 के बाद चुनाव आयोग ने 16। राजनीतिक दलों के स्टेट्स को अपग्रेड किया है। और 9 राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेट्स के मद्देनजर ही फैसला लिया है।

दरअसल इन तीनों पार्टीयों का वोट शेयर देशभर में 6 फीसदी से कम हुआ है। अब देश में 6 ही राष्ट्रीय पार्टी बची हुई हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी , भातीी कम्यूनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) नेशनल पीपुल्स पार्टी, और अब जुडी आम आदमी पार्टी समीकरण के बाद राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल पार्टी (आरएलडी) चौ. अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी की पार्टी का तो यूपी से भी क्षेत्रीय दल का तक दर्जा खत्म हो गया है। टूटी राजनीतिक गठजोड माला को पिरोने की कवायद में बिहार के।

सीएम नीतीश कुमार दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं तीनों क्षेत्रीय दल में तब्दील पार्टी प्रमुखों ने दोबारा राष्ट्रीय दल मे तब्दील करने के लिए हुंकार भरी है। अब देखना ये है कि उच्च पदों की गरिमा जिनमें न्यायपालिका, समेत सरकारी संस्थानों को चैलेंज करने की नई परिपाटी की आधारशिला रखी जाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल विपक्षी पार्टी यों के तमाम सत्ता के समीकरण बिगड गए हैं।

दरअसल इन तीनों पार्टीयों का वोट शेयर देशभर में 6 फीसदी से कम हुआ है। अब देश में 6 ही राष्ट्रीय पार्टी बची हुई हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी , भातीी कम्यूनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) नेशनल पीपुल्स पार्टी, और अब जुडी आम आदमी पार्टी समीकरण के बाद राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल पार्टी (आरएलडी) चौ. अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी की पार्टी का तो यूपी से भी क्षेत्रीय दल का तक दर्जा खत्म हो गया है। टूटी राजनीतिक गठजोड माला को पिरोने की कवायद में बिहार के।

इनसाइड

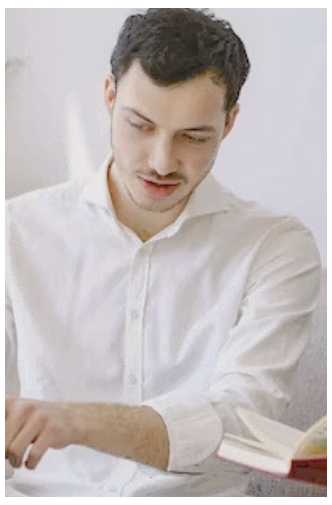

ऑफिस में महिला कलीग से बात करें तो जरूर रखें इन बातों का ख्याल, बन जाएंगे उनके फेवरेट, बॉन्डिंग भी होगी स्ट्रॉन्ग

ऑफिस में फीमेल कलीग से बात करना कई पुरुषों के लिए आसान नहीं होता है. ऐसे में पुरुष महिला कलीग के सामने भाषा पर ध्यान देने से लेकर स्माइल करने, मोटिवेट रखने जैसे कुछ टिप्स अपनाकर उनके साथ हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं.

ऑफिस में पुरुष और महिला कलीग्स दोनों मौजूद रहते हैं. ऐसे में कई मेल कलीग्स आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं मगर फीमेल कलीग्स के सामने ज्यादातर पुरुष असहज महसूस करते हैं. आप चाहें तो महिला सहकर्मी से बात करते समय कुछ चीजों का खास ख्याल रखकर ना सिर्फ उनके फेवरेट बन सकते हैं, बल्कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.

फीमेल कलीग के सामने कई सारे पुरुष नर्वस हो जाते हैं, जिसके चलते वे महिलाओं से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है. ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप फीमेल कलीग्स से बेस्ट बॉन्डिंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऑफिस में महिला कलीग से बात करने के टिप्स.

भाषा पर संयम रखें

अपने ऑफिस की किसी भी महिला कर्मचारी से बात करते समय पुरुषों को भाषा पर ध्यान देना जरूरी होता है. दरअसल, पुरुष आपस में तुम या तू करके बात करते हैं मगर महिलाओं के सामने ऐसे पेश आने से आपका इम्प्रेशन खराब हो सकता है. वहीं, फीमेल कलीग के सामने बॉडी लैंग्वेज भी सही रखें, जिससे वे भी आपके सामने सहज महसूस कर सकें.

स्माइल करना है जरूरी

अगर आप महिला कलीग से बात करने में असहज महसूस करते हैं तो आप उन्हें दूर से देखकर मुस्कुरा भी सकते हैं. फीमेल कलीग से आई कॉन्टैक्ट होने पर आपकी एक मुस्कान भी काफी है. इससे आप बिना बोले उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकेंगे और आपका रिश्ता मजबूत होने लगेगा.

काम पर ध्यान दें

महिला कलीग से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए आप काम में उनकी मदद मांग सकते हैं. इससे ना सिर्फ ऑफिस का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, बल्कि काम के बीच में हंसी-मजाक करने से आपका रिश्ता भी बेहतर होने लगेगा. लेकिन, काम के दौरान पॉजिटिविटी बरकरार रखें और साथी कलीग की बुराई करने से बचें.

मोटिवेट करें

महिला कलीग को काम के प्रति मोटिवेट रखकर आप उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं. इससे फीमेल कलीग की ऑफिस परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगेगी. साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप फीमेल कलीग के फेवरेट बन जाएंगे.

टी ब्रेक पर जाएं

ऑफिस के काम में लोगों को फीमेल कलीग से बात करने का मौका कम ही मिलता है. ऐसे में आप महिला कलीग को चाय या कॉफी का ऑफर दे सकते हैं मगर ध्यान रहे कि हर रोज महिला कलीग के साथ टी ब्रेक पर ना जाएं. इससे फीमेल कलीग के साथ आप बेस्ट प्रोफेशनल रिलेशन बना सकेंगे.

कस्तूरबा गांधी: बापू से लड़ीं-तर्क किए

नहीं माना मनमाना आदेश, पर हर फैसले में साथ रहीं, उजागर नहीं किए मतभेद

कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के सत्याग्रह समर्पण और त्याग में बराबर की सहभागी बनी। कुछ लोगों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल माना तो कुछ ने सिर पर पल्लू लिए पति के पीछे-पीछे चलने वाली नितांत एक घरेलू महिला जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी।

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। महान बने, देशवासियों के लिए भगवान बने। राष्ट्रपिता कहलाए, शांति और आजादी के दूत बने, लेकिन क्या यह सब उन्होंने अकेले अपने दम पर हासिल किया या फिर कोई मजबूत सहारा बन सालों साल खड़ा रहा?

इसके जवाब में एक नाम है- कस्तूरबा गांधी। यह वही नाम है, जो गांधी के सत्याग्रह, समर्पण और त्याग में बराबर का सहभागी बना। उनके हर कदम का साथी बना। तर्क-वितर्क किया, लेकिन हर फैसले को स्वीकार किया। कुछ लोगों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना तो कुछ ने सिर पर पल्लू लिए पति के पीछे-पीछे चलने वाली नितांत एक घरेलू महिला, जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी।

आज कस्तूरबा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर पढ़िए कि 'बा' क्या थीं- एक घरेलू महिला या महिला सशक्तिकरण की मिसाल...

कस्तूरबा गांधी के जीवन पर किताब 'द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा' लिखने वाली लेखिका नीलिमा डालमिया आधार कहती हैं कि 'बा' बेहद पारंपरिक और पतिव्रता स्त्री थीं। शादी से लेकर आखिरी सांस तक गांधी के हर फैसले में साथ खड़ी रहीं। अच्छी पत्नी और मां बनने की कसौटी पर खरी उतरने में लगी रहीं।

घर संभाला, आश्रम संभाले। न सिर्फ अपने बच्चों, बल्कि आंदोलनकारियों पर भी ममता लुटाई। बा ने गांधी जी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को और मजबूत बनाया। महिलाओं को इसमें जोड़ा, जिससे हिंदुस्तान का घर-घर आजादी के इस आंदोलन से जुड़ा।

नीलिमा कहती हैं कि जब मैंने शोध किया तो हैरान रह गई। कस्तूरबा के बारे में सब सोचते हैं कि वह एक घरेलू महिला थीं, जो सिर्फ अपने पति का अनुसरण करती थी, जिनकी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं थी, जबकि वे इसके बिल्कुल विपरीत थीं। वह बहुत आत्मनिर्भर और साहसी महिला थीं, जो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं।

वक्त के सितम भी सहे...

वह आगे बताती हैं कि आज ही के दिन, यानी 11 अप्रैल, 1869 में उनका जन्म हुआ। कस्तूरबा एक बेहद धनी परिवार की बेटी थी। उनके पिता पोरबंदर के पूर्व मेयर गोकुलदास मकनजी कपाड़िया बेहद सम्मानित व्यापारी थे, जिनका विदेशों में कपड़े, अनाज और कॉटन का व्यापार था। समुद्र में उनके जहाज चलते थे। चार भाइयों की इकलौती बहन थीं। बहुत लाड-प्यार से पली-बढ़ीं, लेकिन गांधी परिवार में आने के बाद वक्त और गांधी दोनों के अत्याचार सहने पड़े।

जब 13 साल की उम्र में शादी कर मोहनदास की पत्नी बनी, तब कस्तूरबा मन से चंचल, लेकिन स्वभाव से समझदार व समर्पित पत्नी थीं। इसके इतर, गांधी बेहद डोमिनेटिंग एंड पजेसिव हजबैंड थे। वे कस्तूरबा को अपने मुताबिक चलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए तरह-तरह की जुगत भिड़ाते। गांधी ने कस्तूरबा को आदेश दिया था कि वे बिना उनसे पूछे न कहीं जाएंगी और न कोई काम करेंगी, लेकिन कस्तूरबा ने गांधी के इस आदेश को नहीं माना। इससे चिढ़ कर गांधी कस्तूरबा के प्रति और कठोर हो गए।

गांधी के मनमाने आदेश को नहीं माना..

'सत्य के प्रयोग' में गांधी ने इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है, 'मुझे एक पत्नी व्रत का पालन करना है तो पत्नी को एक पति व्रत का पालन करना चाहिए, यह सोचकर मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालन चाहिए से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर चल पड़ा और मैंने पत्नी की निगरानी शुरू कर दी।

मैं सोचता... मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहां जाती है और क्यों? मेरी अनुमति के बिना वह कहीं नहीं जा सकती, लेकिन कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहां इच्छा होती, वहां मुझसे बिना पूछे जरूर जातीं। मैं जैसे-जैसे दबाव डालता, वैसे-वैसे वह अधिक आजादी से काम लेतीं और उतना ही मैं ज्यादा चिढ़ता।' हालांकि, बाद में गांधीजी ने कहा कि जैसे-जैसे मैं कस्तूरबा को जानता गया, वैसे-वैसे उनके प्रति प्रेम बढ़ता गया और उनका ज्यादा सम्मान करने लगा।

जब बा ने गांधी से कहा- तुम्हें थोड़ी शरम नहीं आती

साउथ अफ्रीका में गांधी जी स्वावलंबन को आगे बढ़ा

रहे थे। घर में नौकर नहीं थे। सभी को अपने काम स्वयं करने होते थे। उस वक्त अभी जैसे टॉयलेट नहीं होते थे, तब मैला खुद साफ कर फेंकना होता था। गांधी ने कस्तूरबा को अपने यहां आए मेहमान का मैला साफ करने को मजबूर किया तो वे गुस्से से फट पड़ी। कहा- बहुत हो चुका, अब वे नहीं करेंगी। इसके बाद दोनों के बीच बुरी तरह झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि गांधी कस्तूरबा को बांह पकड़ कर घर से बाहर निकालने लगे। इसके बाद बापू अपने किए शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने चेहरे पर सख्ती लाता हुए दरवाजा बंद कर दिया।

गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, "यह बिल्कुल वैसा ही था, जैसा मुझे एक अंग्रेज अधिकारी ने ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाला था। कस्तूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिल्ला रहीं थी कि तुम्हें थोड़ी भी लाज शरम नहीं है? तुम अपने आप को इतना भूल गए? मैं कहां जाऊंगी? तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीवी रहते हुए मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने और तुम्हारी ठोकरें खाने के लिए हूं। भगवान के लिए अपना व्यवहार ठीक करो और गेट को बंद कर दो। इस तरह का तमाशा मत खड़ा करो।"

गांधी से लड़ीं, तर्क किए पर साथ नहीं छोड़ा

लेखिका नीलिमा डालमिया आगे बताती हैं कि कई जगहों पर कस्तूरबा और गांधी जी के विचार एक-दूसरे से नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में वह विरोध भी करतीं और अपने तर्क रखतीं। इसके बावजूद वह गांधी के साथ अडिग खड़ी रहतीं। गांधी जी ने कई ऐसे फैसले किए जो अमान्य हो सकते थे, लेकिन बा ने उन्हें माना और गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। मां और पत्नी के रूप में वह हमेशा समर्पित मनस्थिति में रहीं।

गांधी जी की बेटों के प्रति विचारों की असहमति का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के साथ नाम जुड़ने का उन्होंने दोनों पर तक किए, लेकिन कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच मतभेद भी होते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा को कभी बाहर नहीं आने दिया। हर फैसले में गांधी का साथ दिया।

अधिकार जताया, पर शक नहीं किया

आश्रम में गांधी महिलाओं के इर्द गिर्द घिरे रहते, लेकिन कस्तूरबा के मन में जरा भी संदेह नहीं हुआ। नीलिमा एक किस्सा सुनाती हैं, जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तब कैंप में वे बीमार पड़ गए। उस वक्त एक ब्रिटिश महिला मीरा बेन गांधी की विशेष अनुयायी हुआ करती थी। मीरा बेन ने कहा कि गांधी जी उनके साथ रहेंगे ताकि वे अच्छे से देखरेख कर सकें। उस वक्त 'बा' ने अपना अधिकार जताया। कहा- नहीं, वो मेरे साथ रहेंगे और मैं उनका ख्याल रखूंगी।

इसी तरह जब सरला देवी से गांधी का नाम जुड़ा तो उनके करीबी भी चिंतित हो उठे। सबको लगा कि गांधी ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़कर सरला से शादी तो नहीं कर लेंगे! गांधी के पोते तुषार ने एक इंटरव्यू में बताया कि बापू के करीबी लोग कस्तूरबा के पास पहुंचे और उनसे गांधी को समझाने की गुजारिश करने लगे, तब बा ने कहा, "तुम मेरे पति को पहचानते नहीं हो। मेरे पति को जो मुझमें नहीं मिल रहा है, वह दूसरों में ढूढ़ रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, वो कहीं नहीं जाएंगे।"

गांधी को बापू बनाने वाली सशक्त महिला

लेखिका बताती हैं कि एक बार की बात है, जब कस्तूरबा कलकत्ता (अब कोलकाता) में हरिलाल के दूसरे बेटे के जन्म के मौके पर गई थीं, तभी गांधी बीमार हो गए। जब कस्तूरबा को इसका पता चला तो वह लौट आईं। कस्तूरबा को देखकर गांधी जी बिलख पड़े और बोले कि तुम नहीं आती तो मैं मर जाता। दोनों के बीच प्रेम था। कस्तूरबा में पति के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी।

कस्तूरबा ने अपनी आखिरी सांस पुणे की आगाखान डिटेंसन कैंप में बापू की गोद में ली। जब बा का अंतिम संस्कार किया गया तो गांधी वहां तब बैठे रहे, तब तक चिता पूरी नहीं जल गई। जब चिता जल रही थी और गांधी शांत भाव से खड़े-खड़े देख रहे थे, तब किसी ने गांधी जी से कहा- कब तक खड़े रहेंगे थक जाएंगे। तब बापू ने जवाब दिया, '62 साल के साथी को क्या इस तरह छोड़ सकता हूं, यह अंतिम विदाई है। इसके लिए तो बा भी मुझे माफ नहीं करेगी।

गांधी के जीवन में छोड़ गई सूनापन

गांधी ने लिखा, 'बा को हमेशा ये अहसास रहा कि अगर वह चली जाएंगी तो मैं टूट जाउंगा। अगर बा का साथ न होता तो मैं इतना ऊंचा उठ ही नहीं सकता था। यह बा ही थीं, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। नहीं तो भगवान जाने क्या ही होता? मेरी पत्नी मेरे अंतः को जिस प्रकार हिलाती थी, उस प्रकार दुनिया की कोई स्त्री नहीं हिला सकती। वह मेरे जीवन का अविभाज्य अंग थीं, उनके जाने से जो सूनापन पैदा हो गया है, वह कभी भर नहीं सकता।'

लूज हो रहा सेल्फ कॉन्फिडेंस? महिलाएं इन 7 टिप्स की लें मदद, दमदार बन जाएगी पर्सनैलिटी

जिंदगी में सफल और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी होता है. हालांकि कुछ लोगों में कॉन्फीडेंस का लेवल अक्सर कम रहता है. ऐसे में ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देने से लेकर खुद पर विश्वास रखने और आलोचनाओं को नजरअंदाज करके आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनकर उभर सकते हैं.

शानदार पर्सनैलिटी के लिए कॉन्फिडेंस हाई होना बेहद जरूरी होता है. खासकर करियर को बेहतर बनाने में आत्मविश्वास का अहम योगदान होता है. हालांकि कुछ लोगों में अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस (Self confidence) की कमी देखने को मिलती है. ऐसे में अगर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है. तो आप कुछ आसान टिप्स की मदद ले सकते हैं. जिससे आपका आत्मविश्वास मिनटों में बढ़ता दिखाई देने लगेगा.

सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने का काम करता है. ऐसे में आत्मविश्वास को ज्यादातर लोगों का हैप्पीनेस सीक्रेट भी माना जाता है. वहीं कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण लोगों को लाइफ में काफी सफर करना पड़ सकता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के कुछ आसान टिप्स, जिसकी मदद से आप खुशमिजाज और बोल्ड पर्सनैलिटी बनकर उभर सकते हैं.

ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करें

ड्रेसिंग सेंस आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है. ऐसे में अच्छी ड्रेस, मैचिंग फुटवियर और गुड लुक कैरी करके आप अंदर से काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं.

कम्युनिकेशन पर ध्यान दें

कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. ऐसे में अलग-अलग लोगों से बातचीत के दौरान अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करें. इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे.

खुद पर विश्वास रखें

खुद पर भरोसा ना होने पर लोग अक्सर कन्फ्यूज और डल महसूस करते हैं. ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना जरूरी होता है. इसलिए दूसरों की बातों पर गौर करने की बजाए अपने फैसलों का सम्मान करें.

गलतियों से ना डरें

गलतियों के डर से लोग अक्सर कुछ नया करना अवॉइड कर देते हैं. जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है. ऐसे में आलोचनाओं का डट कर सामना करें और हमेशा नया सीखने के प्रति तत्पर रहें. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा.

दूसरों से अलग बनें

कई बार दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में लोग अपनी यूनीक पर्सनैलिटी से समझौता कर लेते हैं. हालांकि खुद को दूसरों से अलग बनाकर आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं. इसलिए किसी को कॉपी करने की बजाए अपनी स्किल्स को निखारने पर फोकस करें.

डर से लड़ें

कई बार हार या आलोचनाओं के डर से लोग अपने दिल की नहीं सुनते हैं. जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुट कर रह जाते हैं. इसलिए डर से भागने की बजाए इसका डट कर सामना करें और अपनी बात रखने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं. इससे आपका कॉन्फिडेंस आसानी से बूस्ट होने लगेगा.

लोगों की बातों को करें नजरअंदाज

कुछ लोग दूसरों की बातों को अक्सर दिल से लगा लेते हैं. जिससे आप खुद अपनी सफलता में बाधक बन जाते हैं. इसलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें और खुद अपनी गलतियों से सीख लेकर जिंदगी में आगे बढ़ें. इससे आप कॉन्फीडेंट और बोल्ड पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे.

50 के बाद भी रहना है हेल्दी, 4 विटामिन्स को करें डाइट में शामिल, कम दिखने लगेगी उम्र, हमेशा रहेंगी फिट

पचास की उम्र के बाद महिलाओं में कमजोरी आने लगती है. ऐसे में महिलाएं अपनी बढ़ती उम्र को कम दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं. वहीं, तमाम नुस्खे आजमाने के बाद भी महिलाएं अपनी ऐज को छुपाने में नाकाम हो जाती हैं. अगर आप 50 की हो रही हैं तो कुछ जरूरी विटामिन्स को डाइट (Diet tips) में एड करके आप उम्र के असर को आसानी से हाइड कर सकती हैं.

50 प्लस वुमेंस में विटामिन की कमी होना काफी आम बात है. ऐसे में विटामिन रिच डाइट को अवॉयड करने से ना सिर्फ महिलाएं फिजिकली वीक महसूस करने लगती हैं, बल्कि आपकी उम्र भी ज्यादा दिखती है. मेडिकलन्यूज़टुडे के मुताबिक, हम आपको बताते हैं 5 एसेंशियल विटामिन सप्लीमेंट्स के नाम, जिनका सेवन करके आप 50 के बाद भी खुद को यंग रख सकती हैं.

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 को एनर्जी का बेस्ट सोर्स माना जाता है. मगर बढ़ती उम्र के साथ शरीर में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलने लगती है. ऐसे में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, अंडा, मीट और खमीर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करके आप विटामिन बी 12 की कमी पूरी कर सकती हैं.

कैल्शियम

कैल्शियम रिच डाइट हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होती है. साथ ही कैल्शियम से भरपूर चीजें खाने से महिलाओं में फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहती है. ऐसे में कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, बीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, बीन्स, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों, सोयाबीन और टोफू का सेवन कर सकती हैं.

विटामिन डी

50 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए विटामिन डी का सेवन भी जरूरी होता है. विटामिन डी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और थकान को दूर रखने में सहायक होता है. वहीं डेयरी प्रोडक्ट, अंडा और फिश को विटामिन डी का बेहतर स्रोत माना जाता है. इसके अलावा बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए आप कुछ देर धूप में भी बैठ सकती हैं.

विटामिन बी 6

50 के बाद शरीर में विटामिन बी 6 की कमी होने लगती है. ऐसे में फिट और हेल्दी रहने के लिए विटामिन बी 6 से भरपूर आहार लेना जरूरी हो जाता है. वहीं गाजर, पालक, केला, दूध, चिकन और कलोंजी को विटामिन बी 6 का बेस्ट सोर्स माना जाता है.

दिल्ली सरकार की 10 करोड़ से अधिक की सभी परियोजनाओं पर जरूरी होगा इंटीग्रिटी पैक्ट, एलजी के आदेश का समझिए

सरकारी परियोजनाओं और खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करने और इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सरकारी खरीद से संबंधित टेंडर के समय सरकार और वेंडर के बीच इंटीग्रिटी पैक्ट को अनिवार्य कर दिया है।

नई दिल्ली। सरकारी परियोजनाओं और खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करने और इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सरकारी खरीद से संबंधित टेंडर के समय सरकार और वेंडर के बीच इंटीग्रिटी पैक्ट को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक की सभी सरकारी योजनाओं अथवा खरीद में इंटीग्रिटी पैक्ट अनिवार्य होगा। अगर इस पैक्ट का किसी वेंडर द्वारा उल्लंघन किया गया तो उसे टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा और उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

भ्रष्टाचार नहीं करने का देना होगा शपथपत्र

दिल्ली सरकार के अधीन सभी विभागों, स्वायत्त निकायों और सिविक एजेंसियों में अब से 10 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं में निविदा लगाने वाले ठेकेदारों एवं विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से सरकार के साथ इंटीग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर करना होगा। इस पैक्ट के तहत बोली लगाने वाले ठेकेदारों सहित दोनों पक्षों के व्यक्ति, अधिकारी को शपथपत्र देना होगा कि वह किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे।

अनुबंध के निष्पादन से संबंधित किसी भी मुद्दे की जांच-पड़ताल के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (इंडिपेंडेंट एक्सटरनल मॉनिटर-आईईएम) भी नियुक्त किए जाएंगे। निविदा से संबंधित दस्तावेज पर आईईएम का भी नाम होगा, जो सीवीसी के पैनल या सरकारी एजेंसियों द्वारा नियुक्त किए गए पैनल से चुने जाएंगे।

हर नियम का किया जाए पालन

एलजी ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निर्देश दिया है कि इस नियम का हर हाल में अक्षरशः पालन किया जाए। एलजी ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2007 में ही इंटीग्रिटी पैक्ट और आईईएम की नियुक्ति के प्रावधान किए जाने थे, लेकिन दिल्ली सरकार के कुछ विभाग और एजेंसियों ने इन दिशा-निर्देशों का पालन 10 साल बाद वर्ष 2017 से करना शुरू किया।

किसी ने नहीं अपनाई ये प्रक्रिया

उन्होंने इस तथ्य पर भी खेद व्यक्त किया है कि साल 2017 के बाद भी लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण विभागों में से किसी ने भी इंटीग्रिटी पैक्ट और आईईएम प्रक्रिया को नहीं अपनाया। इतना ही नहीं, विभागों ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि 50 करोड़ रुपये की तत्कालीन प्रारंभिक सीमा उनकी परियोजनाओं और खरीद पर लागू नहीं होती। इन सभी प्रक्रियाओं पर विराम लगाते हुए उपराज्यपाल ने सरकारी ठेकेदारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित नए प्रस्ताव में तदनुसार सीमा को घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

सूरज की तपिश से नहीं मिलने वाली राहत, दिल्ली में इस सप्ताह 40 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

नई दिल्ली। दिल्ली वासियों को हाल फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। वर्षा का दौर खत्म हो जाने और आने वाले दिनों में भी बरसात के कोई आसार नहीं होने से जल्द ही राजधानी के अलग-अलग स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम 15.7 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 19 से 80 प्रतिशत रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान स्पोर्टस काम्प्लेक्स में 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

शुष्क मौसम की भविष्वाणी

मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, ₹दिल्ली में कम से कम एक सप्ताह के लिए शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के अभाव में अधिकतम तापमान 15-16 अप्रैल तक 38 डिग्री सेल्सियस के निशान तक चले जाने की संभावना है। 17 अप्रैल तक राजधानी में अलग-अलग स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है, लेकिन अभी लू चलने की संभावना नहीं है।

अगले 10 दिन नहीं होगी बूंदाबांदी

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने कहा कि राजधानी में अगले 10 दिनों में मानसून पूर्व गतिविधि देखने की संभावना नहीं है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, अप्रैल के अंत तक लू की स्थिति बनने की संभावना है।

1951 के बाद के 2022 में दूसरा सबसे गर्म रहा अप्रैल

2022 में, दिल्ली ने 1951 के बाद से 40.2 डिग्री सेल्सियस के मासिक औसत अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म अप्रैल रहा था। पिछले साल अप्रैल में नौ दिन लू चली थी, जिसमें चार दिन पहले 10 दिनों में शामिल थे, जो 2010 के बाद से इस महीने में अधिकतम था।

पहले की इम्युनिटी से हो रहा है कोरोना से बचाव, वायरस हुआ कमजोर

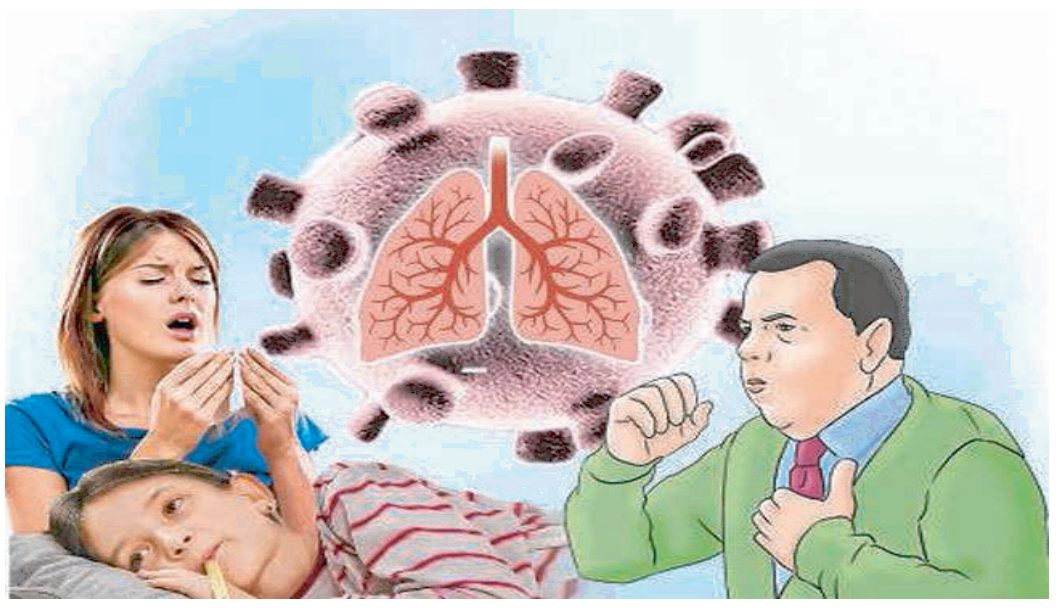

प्राकृतिक संक्रमण व टीका दोनों के प्रभाव के कारण लोगों में कोरोना से बचाव के लिए इम्युनिटी मौजूद है। यही वजह है कि स्वरूप बदलने के बावजूद वायरस कमजोर हुआ है और ज्यादातर लोगों को हल्की बीमारी ही हो रही है।

नई दिल्ली। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण एक बार फिर कोरोना के टीके के लिए आवाज उठने लगी है। कुछ डाक्टर स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की चौथी डोज दिए जाने की मांग भी करने लगे हैं, लेकिन समस्या यह है कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर अब कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं है। इससे टीकाकरण काफी हद तक बंद है। निजी व सरकारी केंद्रों को मिलाकर अभी प्रतिदिन 100 से 125 लोगों को ही टीका लग पा रहा है। जबकि दिल्ली में करीब दो तिहाई वयस्क आबादी को टीके की तीसरी डोज नहीं लग पाई है।

बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों ने भी टीके की तीसरी डोज नहीं ली है। इस बीच जन स्वास्थ्य के विशेषज्ञ डाक्टर कहते हैं कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संक्रमण व टीका दोनों के प्रभाव के कारण लोगों में कोरोना से बचाव के लिए इम्युनिटी मौजूद है। यही वजह है कि स्वरूप बदलने के बावजूद वायरस कमजोर हुआ है और ज्यादातर लोगों को हल्की बीमारी ही हो रही है।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के कम्युनिटी मेडिसिन की पूर्व निदेशक प्रोफेसर डा. सुनीला गर्ग ने कहा लोगों में कोरोना से बचाव के लिए टी-सेल इम्युनिटी है। इससे ही ओमिक्रोन का नया सब-स्ट्रेन का संक्रमण होने के बावजूद हल्की बीमारी हो रही है। टीके की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी जिन लोगों ने अब तक तीसरी डोज नहीं ली है और पहले से कोई बीमारी है तो उन्हें टीके की तीसरी डोज ले लेनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी केंद्रों पर टीका भी उपलब्ध हो।

सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन के विशेषज्ञ डा. जुगल किशोर ने कहा कि बहुत कम मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। जो भर्ती हो रहे हैं उनमें भी ज्यादातर मरीज कैंसर, किडनी, दिल, लिवर की बीमारी से पीड़ित होते हैं। कई बार शरीर में एंटीबाडी अधिक होने से भी नुकसान होता है।

इसलिए अतिरिक्त डोज लेने से पहले एंटीबाडी जांच करा लेनी चाहिए। उम्मीद है कि दो सप्ताह में संक्रमण थम जाएगा। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के विशेषज्ञ डा. संजय राय ने कहा कि कोरोना को मामले अगले कई वर्षों तक घटते बढ़ते रहेंगे। यदि लोगों में इम्युनिटी नहीं होती तो पहले की तरह अधिक संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता।

सामान्य खांसी बुखार की तरह किया जा रहा कोरोना का इलाज, डॉक्टर्स दे रहे ये सलाह

मरीजों को 100 से 103 डिग्री तक बुखार खांसी जुकाम गले में खराश की समस्या देखी जा रही है। बुजुर्ग व पुरानी बीमारियों से पीड़ित कुछ मरीज कोरोना के संक्रमण के कारण भर्ती हो रहे हैं। लेकिन कोई एंटीबायोटिक व एंटीवायरल दवाएं नहीं दी जा रही है।

नई दिल्ली। तीन वर्ष पहले कोरोना के इलाज में एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयों के अंधाधुंध इस्तेमाल से स्वास्थ्य की नई समस्याएं पैदा हो गईं, लेकिन इस बार डाक्टर सतर्क हैं। यही कारण है कि सामान्य खांसी बुखार व वायरल संक्रमण की तरह ही कोरोना के हल्के संक्रमण का इलाज किया जा रहा है। फोर्टिस अस्पताल

के पल्मोनरी मेडिसिन के विशेषज्ञ डा. विकास मौर्या ने कहा कि कोरोना से संक्रमण से ज्यादातर लोगों को हल्की बीमारी हो रही है।

मरीजों को 100 से 103 डिग्री तक बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश की समस्या देखी जा रही है। बुजुर्ग व पुरानी बीमारियों से पीड़ित कुछ मरीज कोरोना के संक्रमण के कारण भर्ती हो रहे हैं। हल्की बीमारी से पीड़ित मरीजों को लक्षण के आधार पर बुखार, खांसी, एलर्जी की दवाएं दी जा रही है। कोई एंटीबायोटिक व एंटीवायरल दवाएं नहीं दी जा रही है। किसी मरीज को फेफड़े में संक्रमण पाए जाने पर जरूरत के मुताबिक रेमडेसिवीर दवा दी जा रही है।

अफवाहों पर न दें ध्यान

एम्स के मेडिसिन विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डा. नीरज निश्चल ने कहा कि कोरोना के इलाज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लक्षण के आधार पर इलाज है। बुखार है तो पैरासिटामोल, गले में खराश व खांसी है तो गार्गल, एंटी एलर्जिक दवा दी जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें।

लोकनायक अस्पताल के एक वरिष्ठ डाक्टर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती कोरोना के ज्यादातर मरीज पहले किसी अन्य बीमारी के कारण भर्ती हुए थे। बाद में उन्हें कोरोना पाजिटिव पाया गया। इसमें कैंसर, किडनी व कई अन्य बीमारियों के मरीज है। कुछ गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की चपेट में आई हैं। युवा और स्वस्थ लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है।

कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को दिया जन्म

मूल रूप से कर्नाटक की ललिता(65) ने 1991 में यौन कर्मियों के बच्चों के लिए की थी शिक्षा-दीक्षा की शुरुआत। आरएमएल अस्पताल में इस वर्ष पहली बार कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला ने सोमवार को बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल के अनुसार जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

घर से निकले मलबे के बंटवारे को लेकर भिड़े दो भाई, दोनों के बीच चाकूबाजी तक पहुंची नौबत; एक की मौत

आली गांव में सोमवार दोपहर भवन निर्माण सामग्री के बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक की मौत हो गई। मृतक के भाई और भतीजों पर उनकी पिटाई करने व चाकू गोद कर हत्या का आरोप है।

नई दिल्ली। आली गांव में सोमवार दोपहर भवन निर्माण सामग्री के बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक की मौत हो गई। मृतक के भाई और भतीजों पर उनकी पिटाई करने व चाकू गोद कर हत्या का आरोप है।

मामले की सूचना के बाद पहुंची जैतपुर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम के लिए कब्जे में लेकर

हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने प्रमोद और उसके दो बेटों आशीष और वरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि मृतक 55 वर्षीय अशोक कुमार अपने परिवार के साथ बदरपुर के आली गांव इलाके में रहते थे, जबकि उनका पैतृक घर एन-ब्लाक, सौरभ विहार में है। इसी इलाके में आरोपित प्रमोद अपने परिवार के साथ रहते हैं।

सहमति से तोड़ा जा रहा था पैतृक घर

दोनों भाइयों की सहमति से पैतृक घर को पुनर्निर्माण के लिए तोड़ा जा रहा है। इससे जो भवन निर्माण सामग्री निकल रही है, उसका बंटवारा दोनों भाइयों में बराबर हो रहा है। इसी बंटवारे को लेकर सोमवार दोपहर करीब 2.12 बजे प्रमोद और अशोक में झगड़ा हो गया। दोनों के बच्चे भी मौके पर आ गए।

एक दिन में करीब एक हजार कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज की मौत हुई।

दिल्ली में कोरोना के मामलों में भारी उछाल, एक दिन में मिले करीब 1 हजार केस; 2 मरीज की मौत

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोरोना के मामलों में भारी उछाल हुआ है। एक दिन में करीब एक हजार कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर भी करीब 26 प्रतिशत पहुंच गई है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के मामलों में भारी उछाल हुआ है। एक दिन में करीब एक हजार कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज की मौत हुई। इसके अलावा दिल्ली में संक्रमण दर भी करीब 26 प्रतिशत पहुंच गई है। बता दें कि सोमवार की तुलना में आज कोरोना के मामलों काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

24 घंटे में मिले 980 मरीज

मंगलवार को दिल्ली में 24 घंटे में 980 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। साथ ही राजधानी में कोरोना के दो मरीजों की मौत भी हुई, लेकिन एक मरीज की मौत में कोरोना प्राथमिक कारण नहीं है। साथ ही कोरोना के एक मरीज की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि, राजधानी में 10 अप्रैल की तुलना में संक्रमण दर में कमी दर्ज की गई।

संक्रमण दर पहुंची 25.98 प्रतिशत

मंगलवार को दिल्ली में संक्रमण दर 25.98 फीसदी रही है, जबकि मंगलवार को 26.58 प्रतिशत थी। बता दें कि 10 अप्रैल को दिल्ली में 484 मामले सामने आए थे, साथ ही 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी हुई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि यहां घनी आबादी है।

गुरुग्राम में भी कोरोना केस में उछाल

गुरुग्राम में भी कोरोना में केस में उछाल देखने को मिला है। पिछले वर्ष 24 अगस्त के बाद मंगलवार को सबसे अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। 266 नए मरीज मिले और 148 स्वस्थ हुए। संक्रमण दर 11.28 दर्ज की गई। 11 दिन में 1711 मरीज मिले हैं और 941 स्वस्थ हुए। एक मरीज की मृत्यु हुई है, जबकि बीते तीन महीने एक जनवरी से 31 मार्च तक 678 मरीज मिले थे। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1068 हो गई है।

दिनदहाड़े हाईवे किनारे पुलिसवाला बन कैफे कर्मी से तमंचे के बल पर मोबाइल, नकदी व बाइक लूटी

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। सहारनपुर से वडोदरा जा रहे बाइक सवार कैफे कर्मी से दो बदमाशों ने दिनदहाड़े हाईवे किनारे बाइक, मोबाइल और आठ हजार रुपये लूट लिए। खुद को पुलिसकर्मी बताकर बदमाशों ने पीड़ित की बाइक को पहले चोरी का बताया और फिर थाने जाने के बहाने उसे दो घंटे तक मधबुन बापूधाम थाना और वर्द्धमानपुरम चौकी के आसपास घुमाते रहे।

मारपीट कर तमंचे के बल पर लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। सात अप्रैल को हुई लूट में सोमवार को पुलिस ने मनमाने तरीके से तहरीर लिखवाकर चोरी और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। सहारनपुर के बेहट में भगवती कालोनी में रहने वाले अभिनव सिंघल वडोदरा (गुजरात) में एक कैफे में काम करते हैं। होली पर घर आए थे और सात अप्रैल की सुबह बाइक लेकर वडोदरा के लिए निकले थे।

गोली मारने की दी धमकी

मेरठ रोड पर दुहाई के पास चाय पीने के लिए रुके थे कि दो व्यक्ति आए और खुद को पुलिसवाला बताकर कहा कि तुम्हारी बाइक चोरी की है। मना करने पर थाने चलने को कहा और दोनों उन्हें बीच में बैठाकर थाना मधुबन बापूधाम के बाहर पहुंचे और यहां से फिर चलने लगे। शक होने पर अभिनव ने पूछा तो पीछे बैठे बदमाश ने उनकी कमर पर तमंचा लगाकर गोली मारने की धमकी दी।

जंगल में ले जाकर दोनों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और पिता सतीश को फोन लगवाकर कहा कि इसके खाते में 15 हजार रुपये डाल दो, नहीं तो हत्या कर देंगे। सतीश ने पैसे न होने की बात कही तो बदमाश आठ हजार रुपये समेत पर्स, मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हो गए। अभिनव राहगीरों से पूछकर गुलधर स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से सहारनपुर लौटे। अगले दिन पिता के साथ गाजियाबाद आए।

कैमरों की मदद से बदमाशों तक पहुंची पुलिस

दो दिन तक पुलिस ने उन्हें साथ लेकर घटनास्थल की शुरुआत से अंत तक कई बार जाकर पड़ताल की। सतीश ने बताया कि कैमरों की फुटेज आदि के आधार पर पुलिस ने बदमाशों को खोज लिया, उनसे मोबाइल व बाइक भी बरामद कर ली। सतीश का कहना है कि उन्होंने पुलिस के बताए अनुसार ही शिकायत लिखी थी। अभी तक पुलिस घटना को छोटा दिखाने के लिए डकैती को लूट और लूट को चोरी में दर्ज करती थी और पर्दाफाश मूल घटना के रूप में ही किया जाता था।

इस घटना में बदमाशों पर शिकंजा कसने के बाद भी पुलिस ने मनमाने तरीके से तहरीर लिखवाकर दिनदहाड़े हुई लूट को छिपाने की कोशिश की। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। जल्द ही मामले का पर्दाफाश करेंगे। यदि बयानों में पीड़ित लूट की बात कहते हैं तो मामले को तरमीम किया जाएगा।

चार माह से बेटे ने नहीं ली खबर, घर में मिला बुजुर्ग मां का सड़ा हुआ शव, अकेली रहती थी सेवानिवृत्त डॉक्टर

नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बेटे और पति से अलग रह रही सेवानिवृत डाक्टर का घर में सड़ा हुआ शव मिला है। सेवानिवृत्त महिला डॉक्टर बेटे और पति से अलग रहती थीं। 20 दिन पहले मौत की आशंका जताई जा रही है। फोन नहीं लगने पर बीटा-1 पहुंचे गाजियाबाद निवासी बेटे-बहू तब हुई मौत की जानकारी

ग्रेटर नोएडा में बेटे और पति से अलग रही सेवानिवृत्त डॉक्टर अमिया कुमारी सिन्हा (70) का शव सड़ी गली हालत में उनके घर से बरामद हुआ। करीब चार माह से उनकी बात गाजियाबाद निवासी बेटे और बहू से नहीं हुई थी। फोन नहीं लगने पर रविवार रात बेटे और बहू बीटा-1 स्थित घर पहुंचे थे। घर में शव देखने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने लगभग 20 दिन पहले मौत की आशंका जताई है। वहीं, फोरेंसिक टीम ने भी मौका मुआयना कर जांच की है। करीब तीन दशक पहले महिला के पति से संबंध विच्छेद हो गए थे। बीटा-2 थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि अमिया कुमारी सिन्हा बिहार के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर थीं।

उन्होंने बीटा-1 सेक्टर में घर बनाया था। बेटा प्रणव रंजन सिन्हा गाजियाबाद के वैशाली में रहता है। प्रणव और उसकी पत्नी गाजियाबाद में ही नौकरी करते हैं। प्रणव ने पुलिस को बताया कि वह कई दिनों से मां के मोबाइल पर कॉल कर रहा था। कई बार कॉल की तो फोन नहीं उठा था।

उसने बताया कि मां अकसर नाराज होकर फोन उठाना बंदकर देती थी। मगर कई दिन से फोन नहीं लगने पर वह पत्नी और सास को लेकर रविवार रात बीटा-1 स्थित मां के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर नहीं खुला। दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर मां का शव पड़ा हुआ था।

4 लाख रुपये का लालच दिखा थमाई कागज की गड्डी, बैंक में घूम रहे टप्पेबाजों ने उड़ाए करीब 50 हजार

गाजियाबाद में बैंक में घूम रहे टप्पेबाजों ने 4 लाख रुपये की लालच देकर 49 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। कोटगांव फाटक के पास रहने वाला राजन सीतामढ़ी (बिहार) में रहने वाले चाचा सुरेश के खाते में पैसे जमा कराने गया था।

गाजियाबाद। टप्पेबाज एटीएम के बाहर ही नहीं अब बैंक के अंदर भी घूम रहे हैं। बैंक आफ बडौद्रा की गांधीनगर शाखा में सोमवार को पैसा जमा कराने गए 12वीं के छात्र को चार लाख रुपये का लालच दे दो टप्पेबाज 49 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। थाना सिहानी गेट पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

कोटगांव फाटक के पास रहने वाला राजन सीतामढ़ी (बिहार) में रहने वाले चाचा सुरेश के खाते में पैसे जमा कराने गया था। फार्म भरने के दौरान एक व्यक्ति आया और पूछा कि फार्म भर लेते हो गया। मुझे चार लाख रुपये जमा कराने है। पास में बैठा दूसरा व्यक्ति बोला हो जाएंगे, लेकिन पैन व आधार कार्ड लगता है। पहले ने कहा कि उसके पास कार्ड नहीं है तो दूसरे ने कहा कि 50 हजार रुपये कमीशन लगेगा।

हम दोनों अपने कार्ड से करा देंगे। इतना कहकर पहले व्यक्ति को बाहर भेज दिया। जालसाज ने राजन को 25-25 हजार रुपये के कमीशन का झांसा दिया और उसे बाहर ले गया। यहां उसने दो गड्डी दिखाईं, जिनमें दो-दो हजार रुपये के नोट दिखाई दिए। दूसरे जालसाज ने उससे पैसे लिए और कहा कि तुम यहीं रुको हम पैसे जमा कराके आते हैं। गड्डी देने वाले ने रोका और कहा कि कुछ रुपये दे दो, मैं कैसे विश्वास कर लूं।

फिर दो लाख के लालच में फंसाया

दूसरे व्यक्ति ने अपने पास से 33 हजार रुपये और राजन से 10 हजार रुपये लेकर उसे दे दिए और दोनों बैंक की ओर चले गए। बैंक के पास जाकर उसने राजन की पैंट में दोनो गड्डियां घुसा दीं और बोला कि निकालना नहीं। लोगों ने देख लिया तो लूट लेंगे। राजन से बचे हुए 39 हजार रुपये लेकर कहा कि आगे एसबीआई के सामने खड़े हो जाना, मैं उसके खाते में सिर्फ इतने रुपये जमा कराऊंगा। बाकी रुपये हम लोग रख लेंगे।

20 मिनट तक इंतजार करने के बाद राजन ने गड्डी खोली तो कागज के टुकड़े निकले। पीड़ित ने दोनों को काफी देर तक खोजा। नहीं मिलने पर परिवार को बताया और फिर पुलिस को सूचना दी। गुरुग्राम के एसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा कि बैंक से कैमरों की फुटेज मांगी है। आसपास के क्षेत्र में लगे कैमरे भी खंगाल रहे हैं। पहचान कर टप्पेबाजों को जल्द गिरफ्तार करेंगे।

फॉर्च्यूनर कार में घूमकर आइपीएल में सट्टा लगवाने वाले 2 गिरफ्तार, पुलिस को गाड़ी से मिले कई चेक

श्याम पार्क एक्सटेंशन में सड़क किनारे एक कार में दो लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहिबाबाद ने टीम के साथ मौके पहुंचे तो सूचना सही मिली। पुलिस ने मौके से कार सवार दो युवकों को दबोचा।

गाजियाबाद। साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के श्याम पार्क एक्सटेंशन में पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार में घूमकर आइपीएल मैच पर सट्टा लगवाने वाले दो सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 35 हजार रुपये, कसिनो क्वाइन, चार मोबाइल, 10 डेबिट-क्रेडिट कार्ड बरामद किया है।

पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन विवेक चंद यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि श्याम पार्क एक्सटेंशन में सड़क किनारे एक कार में दो लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहिबाबाद ने टीम के साथ मौके पहुंचे तो सूचना सही मिली। पुलिस ने मौके से कार सवार दो युवकों को दबोचा।

पकड़े गए आरोपित टीला मोड़ थाना क्षेत्र के रिस्तल का सोनू कसाना और फर्रुखनगर का राहुल कसाना है। दोनों आनलाइन सट्टा लगवा रहे थे। आसपास अन्य लोग भी खड़े थे। पुलिस को देखकर मौके से भाग गए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वाट्सएप पर भी सट्टा लगवाते थे। उनके मोबाइल से सट्टे का लेनदेन और दाव के चैट भी पुलिस को मिले हैं। कार से कई चेक भी पुलिस को मिले। हैं। उन्होंने बताया कि सट्टा लगवाने में उनके चार अन्य साथी भी शामिल हैं। उन्होंने पुलिस को सभी के नाम बताए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

इनसाइड

तीन दुकानों में लगी आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

गाजियाबाद स्थित हापुड़ रोड पर तीन दुकान में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पानी की कोशिश कर रही हैं।

मोदीनगर। गाजियाबाद में हापुड़ रोड पर स्थित तीन दुकानों में मंगलवार को अचानक आग लग गई। दुकानों में अचानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं, इस हादसे में किसी भी हताहत की कोई जानकारी सामने नहीं है।

ESIC अस्पताल में विजिलेंस टीम ने 4 घंटे खंगाले दस्तावेज, कई अधिकारी जांच की रडार पर

पिछले एक माह में रेफर मरीजों के कागजों को जब्त कर लिया। इसके बाद टीम चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीलम नाग के कार्यालय में पहुंची और चिकित्सा अधीक्षक से पूछताछ की। एडमिन विभाग के सहायक निदेशक राज रंजन राय छुट्टी पर थे।

गाजियाबाद। राजेंद्र नगर के राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआइसी) अस्पताल में सोमवार को विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। टीम ने चार घंटे तक कागजों को खंगाला। विजिलेंस को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। अस्पताल के कई अधिकारी जांच की रडार पर हैं। अधिकारियों पर मरीजों को रेफर करने के बाद पैनल अस्पताल से कमीशन लेने और थर्ड पार्टी स्टाफ रखने के बदले में मोटा कमीशन लेने सहित विभिन्न आरोप है। ईएसआइसी मुख्यालय पंचदीप भवन से विजिलेंस विभाग से प्रमोद शर्मा सहित तीन अधिकारी सुबह 10:30 बजे राजेंद्र नगर अस्पताल पहुंचे। विजिलेंस टीम ने इमरजेंसी में दस्तावेजों की जांच की। रिफरल विभाग रूपम नंबर 30 में कागजों को खंगाला। पिछले एक माह में रेफर मरीजों के कागजों को जब्त कर लिया। इसके बाद टीम चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीलम नाग के कार्यालय में पहुंची।

मंडी में अराजकता फैलाने वाले 6 व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी, 50 का सामान जब्त

गाजियाबाद नवीन फल व सब्जी मंडी में सोमवार को अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मंडी समिति ने कार्रवाई करते हुए 6 व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति रिपोर्ट तैयार कर ली है। साथ ही समिति ने 50 से व्यापारियों का सामन जब्त कर लिया है।

गाजियाबाद। साहिबाबाद नवीन फल व सब्जी मंडी में सोमवार को अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मंडी समिति ने कार्रवाई। अवैध व्यापार कराने के बदले में कमीशन ले रहे छह व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति रिपोर्ट बनाई गई है। 50 से अधिक ठेली-पटरी वालों का सामान जब्त कर लिया गया। 100 से ज्यादा लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

सुबह चार बजे मंडी खुलती है। बाजार से कम दाम पर और ताजा सब्जी व फल मिलने के कारण यहां अधिक संख्या में सुबह छह बजे से ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। दूर-दूर से फल व सब्जी के ट्रक आते हैं। फुटकर व्यापारी भी फल व सब्जी बेचते हैं। कुछ लोगों ने मंडी की सड़कों पर कब्जा कर लिया था। मंडी में ग्राहक और व्यापारी दोनों परेशान थे। दैनिक जागरण ने इस समस्या पर एजेंडाबेस रिपोर्टिंग की। उच्चाधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेकर मंडी समिति को कार्रवाई का आदेश दिया। सोमवार को मंडी सचिव विश्वेंद्र कुमार सुरक्षाकर्मियों के साथ कार्रवाई करने निकले, जो लोग चेतावनी के बाद भी बाज नहीं आए ऐसे 50 से अधिक लोगों का सामान जब्त कर लिया गया। 100 से ज्यादा लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यदि ये लोग दोबारा से अव्यवस्था फैलाते हुए मिलते हैं तो इनका सामान भी जब्त किया जाएगा।

व्यापारियों को मिलेगा सबक

मंडी सचिव विश्वेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ व्यापारी अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण कराने के बदले में अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे छह व्यापारियों को चिह्नित किया गया है। उनके लाइसेंस निरस्त करने के कागज तैयार कर लिए गए हैं। जब तक मंडी की व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट आती है तब तक कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

मंडी व्यापारी शादाब ने कहा- मंडी में अब व्यवस्था पटरी पर है। समिति ने जाम की समस्या खत्म करा दी है। अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, राजेंद्र शर्मा नाम के व्यपारी ने कहा- मंडी समिति के कार्रवाई करने पर ग्राहकों को फायदा मिलेगा। लोगों को आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। व्यवस्था बनाकर लोगों को सब्जी व फल बेचनी चाहिए।

खाना देने के बहाने अस्पताल स्टाफ के सदस्य ने महिला मरीज से की छेड़छाड़, आरोपित गिरफ्तार

गाजियाबाद में पुलिस ने महिला रोगी को खाना देने के बहाने छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

गाजियाबाद। साहिबाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर-4 के एक अस्पताल में भर्ती महिला मरीज से स्टाफ ने छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपित रूम से निकलकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

लिंक रोड थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी की तबियत खराब था। उन्होंने वैशाली सेक्टर चार के एक अस्पताल में आठ अप्रैल को भर्ती कराया।

4 लाख रुपये का लालच दिखा थमाई कागज की गडडी

आरोप है कि नौ अप्रैल की रात आठ बजे अस्पताल में खाना देने वाले स्टाफ विशाल रूम में घुस गया। पत्नी को अकेला देखकर छेड़छाड़ करने लगा। जबरन हाथ पकड़ लिया। महिला के चीखने चिल्लाने पर आरोप रूम से निकलकर बाहर की ओर भाग गया।

वह अस्पताल पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपित विशाल को अपने साथ थाने ले गई। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

पूर्व में रेस्टोरेंट में हुई थी बच्ची से छेड़छाड़

करीब 10 दिन पूर्व कौशांबी थाना क्षेत्र के ही वैशाली सेक्टर चार के एक नामी रेस्टोरेंट में दिल्ली का परिवार खाना खाने आया था। जहां पर वेटर ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ की थी। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इनसाइड

हीरो स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले कितनी दमदार है होंडा शाइन 100, कौन किस मामले में बेहतर

भारतीय बाजार में हीरो और होंडा दोनों कंपनियों की बाइक्स अधिक सेल होती है। हाल के दिनों में लॉन्च की गई होंडा शाइन 100 का मुकाबला स्प्लेंडर प्लस से है। आज हम आपके लिए Honda Shine 100 vs Hero Splendor Plus की तुलना लेकर आए हैं।

नई दिल्ली। हीरो और होंडा दोनों ही कंपनियां भारतीय बाजार में आज से ही नहीं कई सालों से राज करते आ रही है। ये तो आपने भी खुद अनुभव किया होगा कि भारतीय सड़कों पर अधिकतर हीरो और होंडा की बाइक्स दिखाई देती है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने शाइन 100 के लॉन्च के साथ 100 सीसी मोटरसाइकिल कैटेगरी में कदम रखा है। नई 2023 होंडा शाइन 100 को भारतीय बाजार में 64,900 रुपये एक्स-शोरूम में लॉन्च किया गया है और इसका मुकाबला स्प्लेंडर प्लस से है। आज हम आपके लिए एंट्री-लेवल 100cc कम्यूटर मोटरसाइकिल की तुलना लेकर आए हैं।

Honda Shine 100 vs Hero Splendor Plus डिजाइन और कलर

डिजाइन के मामले में, इन दोनों मोटरसाइकिल का लुक ही लोगों को अधिक पसंद आता है। वाहन निर्माता कंपनी ने होंडा शाइन 100 को पांच कलर ऑप्शन में पेश किया है, जबकि स्प्लेंडर प्लस बारह पेंट कलर ऑप्शन में ही आती है।

Honda Shine 100 vs Hero Splendor Plus इंजन और गियरबॉक्स

Honda Shine 100 में 99.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो 7.6 bhp और 8.05 Nm का टार्क जनरेट करती है। दूसरी ओर, हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड मोटर मिलता है जो 7.9 bhp और 8.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। ये दोनों मोटरसाइकिलें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ी हैं। इसके अलावा ये 60-70 kmpl का माइलेज देती है। नई होंडा शाइन 100 के साथ-साथ हीरो स्प्लेंडर प्लस स्पोर्ट टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर में डुअल स्प्रिंग-लोडेड शॉक एब्जॉर्बर के साथ आती है। दोनों में ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दोनों ओर ड्रम ब्रेक द्वारा ब्रेकिंग ड्यूटी है।

डेली के काम झटपट निपटाने हीरो ने लॉन्च की 2 नई इलेक्ट्रिक साइकिल

नई दिल्ली. भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक साइकिल सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी हीरो लेक्ट्रो (Hero Lectro) ने दो नई ई-साइकिल लॉन्च की हैं। इन साइकिल के नॉडल H3 और H5 हैं। दोनों ई-साइकिल GEMTEC पावर्ड हैं। H3 की कीमत 27,499 और H5 की कीमत 28,499 रुपए है। H3 को दो कलर ऑप्शन ब्लिसफुल ब्लैक-ग्रीन और ब्लेजिंग ब्लैक-रेड में खरीद पाएंगे। वहीं, H5 को ग्रूवी ग्रीन और ग्लोरियस ग्रे कलर में खरीद सकते हैं। दोनों साइकिल की सिंगल चार्ज पर रेंज 30km तक है। हीरो लेक्ट्रो की इन न्यू इलेक्ट्रिक साइकिलों को मजबूती देने के साथ हल्का रखने के लिए GEMTEC मैटिरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक नई राइड ज्योमेट्री और स्मार्ट फिट एर्गोनॉमिक्स मिलता है, जिसे हीरो साइकिल्स के R&D सेंटर में डिजाइन और डेवलप किया गया है। इन GEMTEC ई-साइकिलों को कंपनी की D2C वेबसाइट के साथ-साथ हीरो लेक्ट्रो के 600 से ज्यादा डीलरों के नेटवर्क, ई-कॉमर्स चैनलों से खरीद सकते हैं।

2028 तक हर साल नई कार लेकर आएगी होंडा, कंपनी ने किया एलान

जापानी वाहन निर्माता कंपनी Honda ने एलान किया है कि वह आने वाले सालों में कई नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इसमें SUV से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक शामिल हैं। ये जानकारी कंपनी के एक आला अधिकारी ने दी है।

नई दिल्ली। जापानी कार निर्माता कंपनी Honda भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने की ओर रुख कर रही है। कंपनी ने एलान किया है कि वो 2028 तक हर साल नई कार पेश करेगी। कंपनी का उद्देश्य भारत में अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना है। अभी तक Honda देश में केवल सेडान और कॉम्पैक्ट सेडान श्रेणी की कार बेचती है। क्या कंपनी आने वाले सालों में कोई इलेक्ट्रिक कार या फिर SUV भी लॉन्च करने वाली है, आइए जान लेते हैं।

क्या है कंपनी का प्लान

जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा के एक आला अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि वो भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए कंपनी अगले तीन से पांच साल तक प्रत्येक वर्ष एक नया उत्पाद पेश करेगी। ये या तो पूर्णतया नए मॉडल होंगे या फिर अपडेट।

मौजूदा स्थिति की बात करें तो Honda की भारत में 2.5 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत में होंडा को चालू वित्त वर्ष में लगभग 92,000 यूनिट्स के साथ 8 प्रतिशत उछाल की उम्मीद है। साथ ही कंपनी भारत में निर्मित कारों को तुर्की, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम एशिया को भी निर्यात कर रही है। कंपनी ने इस वर्ष कुल 23 हजार यूनिट्स को निर्यात किया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक है।

लॉन्च होगी SUV और इलेक्ट्रिक कार?

कंपनी के उपाध्यक्ष (मार्केटिंग एंड सेल्स) कुनाल बहल ने कहा कि Honda अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में एक SUV कार को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। वहीं उन्होने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक कार को भी लॉन्च करने की योजना में है।

आपको बता दें कि उन्होने इन कार को लॉन्च करने की कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं बताई है। मौजूदा समय में कंपनी देश में केवल सेडान कारों को ही बेच रही है। हाल ही में उसने अपनी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार Honda City को हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया था।

कंपनी के उपाध्यक्ष (मार्केटिंग एंड सेल्स) कुनाल बहल ने कहा कि Honda अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में एक SUV कार को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। वहीं उन्होने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक कार को भी लॉन्च करने की योजना में है।

क्या होता है कारों में A-B-C-D और J सेगमेंट, आसान भाषा में समझिए इनका अंतर

कार निर्माता कंपनी अपने वाहनों को अलग-अलग सेग्मेंट में वर्गीकृत करके बेचती हैं। इनमें ABCD और J सेग्मेंट शामिल हैं। हम आपको इन सभी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। कार के सेगमेंट को लेकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए।

नई दिल्ली। सभी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कारों के आकार और डायमेंशन के हिसाब से इन्हें A,B,C,D और J सेगमेंट में वर्गीकृत करती हैं। क्या आपको इन सभी टर्म के बारे में पता है? अगर जवाब है नहीं, तो आप इस लेख को पढ़ने के बाद कारों के इन सभी सेगमेंट के बारे में जान जाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप जिस कार के मालिक हैं, वो किस श्रेणी में आती है।

आकार और डायमेंशन के हिसाब से होता है वर्गीकरण

कंपनी जब किसी कार को डिजाइन करती है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि इसे किन ग्राहकों के लिए बनाया जाय और इसका आकार और डायमेंशन क्या होना चाहिए। इसलिए ही कारों को A,B,C,D और J सेगमेंट में बांटा गया है। आपको बता दें कि सबसे छोटी कारों को A, वहीं सबसे बड़े आकार की गाड़ियों को J सेगमेंट में शामिल किया जाता है। आइए, आपको अब A से लेकर J सेगमेंट को आसान भाषा में समझाते हैं।

A-सेगमेंट

ये गाड़ियां आकार में छोटी होती हैं और शहरी रास्तों के लिए ठीक होती हैं। इन्हें अच्छी सड़कों पर आसानी से चलाया जा सकता है। A-सेगमेंट की गाड़ियों का इंजन और वजन भी हल्का रखा जाता है। इन्हें एंट्री लेवल मॉडल और कॉम्पैक्ट हैचबैक भी कहा जाता है।

B-सेगमेंट

इस सेगमेंट की कारों को स्मॉल हैचबैक और प्रीमियम हैचबैक के नाम से जाना जाता है। A-सेगमेंट की गाड़ियों के मुकाबले ये ज्यादा ऊंची और चौड़ी होती हैं। B-सेगमेंट की कार में 4 लोग आसानी से बैठ जाते हैं।

C-सेगमेंट

इस सेगमेंट की कार की लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन ये कम ऊंची होती है। A और B सेगमेंट के मुकाबले इसमें बैठने के लिए ज्यादा जगह होती है, कारण है कार की ज्यादा लंबाई। C-सेगमेंट की कारों को सेडान के नाम से भी जाना जाता है।

D-सेगमेंट

इस सेगमेंट में मिड साइज फैमली कार और Sedan को शामिल किया जाता है। ये C-सेगमेंट वाली कार के मुकाबले ज्यादा बड़ी और पॉवरफुल होती हैं। श्रेणी में प्रीमियम सेडान कार भी आती हैं।

J-सेगमेंट

Cars की इस श्रेणी को मौजूदा समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इन कारों को SUV यानी Sports utility vehicle कहा जाता है। ये कारें सभी रास्तों पर चलने में सक्षम होती हैं। इनको भी आकार और डायमेंशन के मुताबिक B, C और D श्रेणी में विभाजित किया जाता है।

MPV-सेगमेंट

ये बहुउद्देशीय कार होती हैं। इसी वजह से इन्हे MPV यानी Multi Purpose Vehicle कहा जाता है। बड़े परिवार के लिए ये कार सुविधाजनक रहती है। इन कारों की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ठीक-ठाक होती है।

सेकेंड हैंड कार खरीदते समय इन 5 चीजों का जरूर रखें ख्याल, मिलेगी बेहतरीन डील

सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं उसके मौजूदा इंश्योरेंस पेपर हैं या नहीं। पेपर के साथ यह भी जांच लें कि कार से कोई दुर्घटना या क्लेम तो नहीं किया गया है।

नई दिल्ली। लोग अक्सर सेकेंड हैंड कार खरीदते समय ठग जाते हैं। इसका मुख्य कार गाड़ी संबंधित कम जानकारी होना है। इसलिए अगर आप भी यूज्ड कार खरीदने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें, जहां आपको 5 टिप्स बताएं गए हैं। इनकी मदद से आप अच्छी डील कर सकते हैं।

गाड़ी की कंडीशन चेक करें

अपनी जरूरतों के आधार पर एक सही कार खोजने के बाद कार की स्थिति की जांच करना पहला और महत्वपूर्ण कदम है। कार स्थिति (कंडीशन) का मतलब है कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रेमिंग, टायर, इंजन, माइलेज, ओडोमीटर, टेस्ट ड्राइव और इंजन सहित बहुत सी चीजें हैं जिन्हें चेक करना काफी जरूरी है, ताकि आप कार के हेल्ड की जांच कर सकें। इन पैरामीटर को चेक करने के बाद ही आपको सही कीमत तय कर पाएंगे।

सर्विस हिस्ट्री चेक करें

बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी खरीदने की इतनी जल्दी रहती हैं कि लोग सर्विस हिस्ट्री के बारे में पूछना भूल जाते हैं। आप अगर सेकेंड हैंड कार देखने जा रहे हैं तो संबंधित सर्विस हिस्ट्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें।

इंश्योरेंस पेपर चेक करें

सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं, उसके मौजूदा इंश्योरेंस पेपर हैं या नहीं। पेपर के साथ यह भी जांच लें कि कार से कोई दुर्घटना या क्लेम तो नहीं किया गया है। जानकारी के लिए बता दें, वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी पर इसे देखने का तरीका यह है कि लागू किए गए नो क्लेम बोनस (NCB) प्रतिशत पर ध्यान दें।

टेस्ट ड्राइव जरूर लें

वाहन को खरीदनें से पहले उसके ब्रेक की जाँच करें। कार को ऐसी जगह कम से कम 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं जिसमें ट्रैफिक कम हो। ब्रेक पैडल से किसी भी कंपन या किसी भी अजीब आवाज का एहसास हो तो तुरंत मैकेनिक से परामर्श लें।

2023 Kia Sonet, Seltos और Carens को किया गया अपडेट, कीमत भी बदली

Kia ने अपनी कारों के लाइनअप में BS6 Phase2 compliant के हिसाब से बदलाव कर दिया है। इसके पॉवरट्रेन में हुए बदलाव के साथ कीमतें भी बदल गई हैं साथ ही कंपनी ने अपनी कारों के इंजन को E20 ईंधन के अनुकूल बनाया है।

नई दिल्ली। कोरियन कार निर्माता कंपनी Kia ने अपनी दो SUV और एक MPV कार को नए BS6 फेज-2 नियमों के साथ पेश कर दिया है। इनके इंजन को E20 ईंधन के अनुकूल बनाया गया है। साथ ही कंपनी ने 2023 Kia Seltos,Sonet और Carens की कीमतों में भी बदलाव किया है। ये बदलाव नए पॉवरट्रेन के आने की वजह से हुए हैं। हम आपको इन तीनों कारों के नए इंजन और कीमतों बारे में बताने जा रहे हैं।

2023 Kia Seltos, Sonet और Carens का नया इंजन

कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी kia Sonet में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखा है। साथ ही इसके 1.5 लीटर सीआरडीआई डब्ल्यूजीटी डीजल इंजन को 1.5 लीटर सीआरडीआई वीजीटी के साथ बदल दिया गया है। अब ये इंजन पिछले वाले की अपेक्षा 16 पीएस अधिक पॉवर देता है। वहीं करेंस और सेल्टॉस को नया 1.5 लीटर वाला इंजन दिया गया है।

टाटा मोटर्स की गाड़ियों के पहले से कितनी बढ़ी माइलेज?

ये शक्तिशाली इंजन 160 पीएस की अधिकतम पावर और 253 एनएम का पीक टॉर्क प्रदान करेगा। सेल्टोस और कैरेंस में आने वाला समान पावरट्रेन का पॉवर आउटपुट 1 पीएस से बढ़कर 116 पीएस हो गया है। आपको बता दें कि नए इंजन के साथ इन पूरी रेंज में आईएसजी (आइडल स्टॉप गो) फीचर को स्टैण्डर्ड रूप में दिया गया है।

ये हैं नईकीमतें

नए पॉवरट्रेन के साथ कंपनी ने इन तीनों कार की कीमत भी बदल दी हैं। अब 2023 Kia Sonet को 7.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचा जाएगा, जो कि 14.89 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी ने kia Seltos की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपये रखी है और ये 19.65 लाख रुपये तक जाती है। वहीं Kia Carens को 10.45 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत से लेकर 18.90 लाख रुपये तक रखा गया है।

नए पॉवरट्रेन के साथ कंपनी ने इन तीनों कार की कीमत भी बदल दी हैं। अब 2023 Kia Sonet को 7.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचा जाएगा, जो कि 14.89 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी ने kia Seltos की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपये रखी है और ये 19.65 लाख रुपये तक जाती है।

ई-कॉमर्स में गेम चेंजर 'ओएनडीसी'

डा. अश्विनी महाजन

ओएनडीसी को भी एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है जो उपभोक्ताओं के शोषण को रोक सकती है'

एक दशक से अधिक समय से, ई-कॉमर्स में भारत और दुनिया में भारी वृद्धि देखने को मिली है। भारत में कुल खुदरा व्यापार का लगभग 6.5 प्रतिशत आज ई-कॉमर्स के माध्यम से होता है। ई-कॉमर्स ने जीवन को बेहद आसान बना दिया है, क्योंकि लोगों को घर बैठे एक बटन क्लिक करने पर आसानी से वस्तुएं और सेवाएं मिल जाती हैं। रेल-बस टिकट हो या हवाई यात्रा, होटल बुकिंग हो या टैक्सी, ऑटो से आना-जाना सब कुछ बेहद सुविधाजनक हो गया है। इतना ही नहीं, ई-कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की घरेलू और व्यावसायिक सेवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे पारंपरिक व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है। सवाल केवल कमीशन का नहीं है, ये ई-कॉमर्स कंपनियां डेटा पर अपने एकाधिकार के कारण विभिन्न विक्रेताओं के बीच भेदभाव करती हैं और अपने पसंदीदा विक्रेताओं को वरीयता देती हैं और इस प्रकार अन्य विक्रेताओं को नुकसान होता है। हालांकि, ये कंपनियां अपने ग्राहकों को सस्ता सामान और सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं, लेकिन वास्तव में अपनी आर्थिक ताकत के चलते ये कंपनियां छोटे पारंपरिक दुकानदारों, ट्रैवल एजेंटों आदि को बाजार से बाहर करने के लिए उपभोक्ताओं को भारी छूट देती हैं। अपने स्वयं के पैसे से और ड्राइवरों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने भारी प्रोत्साहन भी दिया। लेकिन अब अपना व्यवसाय स्थापित करने के बाद, उबर सरीखे एग्रीगेट्रों के द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, और ड्राइवरों की कमाई का लगभग एक तिहाई इन एग्रीगेट्रों द्वारा छीन लिया जाता है।

एग्रीगेटर के रूप में काम करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां छोटे वेंडरों और गरीब कामगारों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हड़प रही हैं। ऐसे में उनके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो अपना शोषण होने दें या व्यवसाय छोड़ दें। इतना ही नहीं, ई-कॉमर्स कंपनियों के कैश बर्निंग मॉडल की वजह से परंपरागत कारोबारी भी धंधे से बाहर हो रहे हैं। चाहे किराना दुकान हो या रेडीमेड परिधान की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के शोरूम, या पारंपरिक ट्रैवल एजेंट, ई-कॉमर्स कंपनियों के आने से विभिन्न प्रकार के खुदरा व्यापार में लोगों के रोजगार का क्षरण हुआ है। कहा जा सकता है कि आज का ई-कॉमर्स समावेशी नहीं है। हालांकि, हम ई-कॉमर्स को बंद नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है; सवाल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का है। क्या हम इन ई-कॉमर्स दिग्गजों के लालच पर रोक लगा सकते हैं? इन सवालों के जवाब भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में मिल रहे हैं, जो कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। ओएनडीसी नेटवर्क ई-कॉमर्स को एक चैनल प्रदान कर रहा है। यह खरीददारों और विक्रेताओं के बीच एक कड़ी प्रदान करने की कोशिश करता है, जो शोषणकारी नहीं है। इस प्रणाली में, ई-कॉमर्स कंपनियां डेटा पर एकाधिकार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से विक्रेताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकती हैं। कुल मिलाकर ओएनडीसी एक ऐसा चैनल होगा जिसमें उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के विक्रेता, सेवा प्रदाता आदि को आसानी से खोज सकेंगे और ई-कॉमर्स बाजार में एकाधिकार के बजाय प्रतिस्पर्धा के आधार पर विक्रेताओं के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

ओएनडीसी क्या है? : ओएनडीसी सामान्य ई-कॉमर्स कंपनियों जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। आमतौर पर ई-कॉमर्स कंपनियां एक प्लेटफॉर्म के जरिए काम करती हैं। विक्रेता या सेवा प्रदाता संबंधित प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराते हैं और उन्हें कई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होता है। हालांकि, ये प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को छूट और प्रोत्साहन का लालच देकर, अपनी आर्थिक ताकत के बलबूते उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब उनका व्यवसाय स्थापित हो जाता है, तो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वे उपभोक्ता और विक्रेता, दोनों का शोषण करते हैं। ओएनडीसी वास्तव में विभिन्न प्लेटफार्मों और उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी है जो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता है। अभी तक सामान्य ई-कॉमर्स में विक्रेता और सेवा प्रदात्ताओं को प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होता था, इसलिए वे उन प्लेटफार्मों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता प्लेटफॉर्म पर केवल उन्हीं विक्रेताओं को देख पाते हैं, जो उस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। ओएनडीसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों को ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन ओएनडीसी की शर्त यह है कि इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिन वेंडरों या सेवा प्रदाताओं ने खुद को पंजीकृत कराया है, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं ओएनडीसी पर आने वाले सभी ग्राहकों को दिखाई देंगी। यानी ओएनडीसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ भी अपारदर्शी नहीं है। यह प्रणाली जियोग्राफिक इनफारमेशन सिस्टम (जीआईएस) यानि भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से काम करती है और लाखों विक्रेताओं व करोड़ों उपभोक्ताओं को उनके स्थान यानि लोकेशन के आधार पर सुविधा प्रदान कर सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई उपभोक्ता घर बैठे किसी रेस्तरां से खाना या किराना सामान मंगवाना चाहता है, तो ओएनडीसी प्रणाली में, आस-पास के सभी रेस्तरां या किराना स्टोर तक वो पहुंच सकता है और जो भी वो खरीदना चाहता है, खरीद सकता है। ये सभी विक्रेता और सेवा प्रदाता, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पंजीकृत होने के बावजूद, ओएनडीसी पर संभावित खरीददारों को दिखाई देंगे। हालांकि, जिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वेंडर पंजीकृत हैं, वे वेंडर के साथ अपने समझौते के अनुसार शुल्क लेना जारी रख सकते हैं, लेकिन व्यवसाय लाने के लिए प्लेटफार्मों के बीच प्रतिस्पर्धा से उनका कमीशन अपने आप कम हो सकता है। हर प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने के लिए अपना कमीशन कम रखना चाहेगा। इस प्रकार ओएनडीसी ई-कॉमर्स को प्लेटफार्मों के एकाधिकार से मुक्त करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ओएनडीसी ई-कॉमर्स बिजनेस के नियमों में बदलाव कर सकता है। हालांकि, ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी ओएनडीसी के नेटवर्क में शामिल होने में रुचि दिखाई है और कुछ प्लेटफॉर्म और भुगतान कंपनियां भी ओएनडीसी के साथ पंजीकृत हो रही हैं। हालांकि ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाओं ने अभी तक इस पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है, लेकिन कुछ नई ई-कॉमर्स मोबिलिटी कंपनियां ओएनडीसी में रुचि दिखा रही हैं। ओएनडीसी को हाल ही में पेश किया गया है, ओएनडीसी प्रणाली में बहुत कम व्यवसाय किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यह व्यवसाय निकट भविष्य में तेजी से बढ़ेगा। इससे छोटे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भारी विज्ञापन खर्च के बिना उपभोक्ताओं तक पहुंचना संभव हो सकता है। बड़े या छोटे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सभी पंजीकृत विक्रेता ओएनडीसी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को समान रूप से दिखाई देंगे, क्योंकि ओएनडीसी प्रोटोकॉल विभिन्न विक्रेताओं के बीच अंतर नहीं करता। यदि ओएनडीसी प्रणाली सफल होती है, तो इसके साथ-साथ ई-कॉमर्स के सभी फायदे तो बदस्तूर मिलेंगे ही लेकिन इसकी अधिकांश कमियों से बचा जा सकेगा। गौरतलब है कि अब तक मौजूदा सरकार के तकनीक समर्थित सभी प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। आज यूपीआई दुनिया में एक मिसाल बन चुका है और इसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जल्दी और बिना किसी लागत के संभव हो रहे हैं। आज दुनिया में जितने भी ऑनलाइन लेन-देन होते हैं, उनमें से 40 फीसदी से ज्यादा भारत में हो रहे हैं। इसी तरह, ओएनडीसी को भी एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल उपभोक्ताओं

संपादक की कलम से

डिग्रियों के कंकाल

आम आदमी पार्टी (आप) ने 'डिग्री दिखाओ' अभियान छेड़ा है। सबसे पहले केजरीवाल सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपनी शैक्षिक डिग्रियों का खुलासा किया है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और स्नातकोत्तर दो डिग्रियां विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। 'आप' के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आईआईटी की डिग्री हासिल की। बाद में भारतीय राजस्व सेवा के लिए उनका चयन हो गया। 'आप' एक अपेक्षाकृत नई राजनीतिक पार्टी है। नई पीढ़ी के कुछ शिक्षित लोग इसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री बन सकेंगे या एक सफल राजनीतिज्ञ साबित होंगे अथवा वे राजनीतिक सत्ता के दौरान एक सशक्त और दूरदर्शी प्रशासनिक हस्ती और मंत्री बन सकेंगे, इनकी सिर्फ संभावनाएं ही की जा सकती हैं। करीब छह दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और भारत सरकार में रक्षा और कृषि मंत्री रहे शरद पवार की गणना देश के कद्दावर और चतुर नेताओं में की जाती रही है। पवार अपेक्षाकृत पुरानी पीढ़ी के सफल राजनेता रहे हैं। सिर्फ शैक्षिक डिग्री के आधार पर उन्होंने राजनीतिक मंजर पार नहीं किए हैं। कांग्रेस सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी शरद पवार की जमात के राजनीतिज्ञ हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और उनके समकालीन नेताओं और मंत्रियों की बात छोड़ दें, क्योंकि वह संक्रमण काल था, तो भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी, उनके बाद के प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों, राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे अनंत नेताओं से न तो डिग्रियां पूछी गईं और न ही डिग्रियों के आधार पर उनके राजनीतिक आकलन किए गए, लेकिन वे अपने-अपने कालखंड के कामयाब नेता रहे। लोकतंत्र, राजनीति और शैक्षिक डिग्रियों की कोई आपसी पूरकता ही नहीं है। दरअसल यह केजरीवाल और 'आप' के नेताओं की राजनीतिक अपरिपक्वता ही है कि उन्होंने 'डिग्री दिखाओ' अभियान शुरू किया है। उन्हीं की पार्टी में कई नेताओं की शैक्षिक योग्यता और विलक्षणता सवालिया है।

शायद वे इस अभियान में आगे पेश न किए जाएं। पवार, आजाद और प्रधानमंत्री मोदी सरीखे कद्दावर राष्ट्रीय नेताओं के सामने आतिशी का उदाहरण बेहद बौना है। पवार और गुलाम नबी का मानना है कि डिग्रियां किसी भी आम चुनाव का प्रमुख मुद्दा हो ही नहीं सकतीं। यदि आप डिग्रीधारी हैं, तो प्रोफेसर, अध्यापक, मैनेजर या लिपिक की नौकरी कर सकते हैं। डिग्री दूरदर्शी सोच और विजन की गारंटी नहीं है। यदि लंबे वक्त तक आप बेरोजगार रहे हैं और उनके जैसे असंख्य नौजवान हैं, तो यह राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है। महंगाई इतनी है कि 20,000 रुपए के नौकरीपेशा वाले व्यक्ति का गुजारा और अस्तित्व संकट में है, तो बेशक यह एक और राष्ट्रीय मुद्दा है। किसानी, गरीबी की रेखा और भ्रष्टाचार आदि पर भी चुनाव अभियान बनाए जा सकते हैं। पवार और आजाद का यह भी मानना है कि डिग्री की तरह अडानी समूह की कंपनियों के लेन-देन और व्यापार भी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकते। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिरला रेस्ट हाउस और उनके बंगलों में रहते थे। गांधी के बजाज, डालमिया, सिंघानिया, टाटा आदि औद्योगिक घरानों से भी निकटस्थ संबंध थे। क्या गांधी भ्रष्ट थे? कांग्रेस सरकारों के दौरान धीरूभाई अंबानी के औद्योगिक साम्राज्य का उत्थान हुआ। क्या वे प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट थे? पूर्व सांसद राहुल गांधी के देश-विदेश के दसियों 'अवांछित' उद्योगपतियों से संबंध रहे हैं। मेल-मुलाकातें भी होती रही हैं। क्या इन सबको आम चुनाव 2024 के मुद्दे बनाए जा सकते हैं? इसी तरह 'डिग्री दिखाओ' भी बंजर मुद्दा है।

व्यंग्य

छुट्टियों का व्याकरण

स्कूलों में छुट्टियों का व्याकरण समझने की गलती में शिक्षा विभाग ने पुनः ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 22 जून से 27 जुलाई तक अवकाश का पहाड़ा पढ़ा दिया, जबकि मौसम के हिसाब से यह ऋतु का अप्रत्याशित काल साबित होता है। ऐसे में शिक्षकों की आपत्ति पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। हैरानी यह कि शिमला में बैठा शिक्षा विभाग वार्षिक कैलेंडर में अवकाश की तिथियां घोषित करने से पूर्व स्थिति की मांग और अवकाश की उपयोगिता के बजाय मनमानी लकीरें खींचने लगा है। शायद शिमला में होने के कारण विभाग को यह मालूम नहीं रहता कि बिगड़ा मानसून और जलवायु चक्र के बिगड़े चरित्र के कारण निचले क्षेत्रों में पढ़ाई को मौसम की त्रासदी से बचाने की कितनी आवश्यकता रहती है। पिछले साल भी जुलाई में छुट्टियों की घंटी बजा कर विभाग ने छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों के लिए खतरे बढ़ा दिए थे, लेकिन उससे कोई सबक न लेते हुए ज्यों के त्यों बने रहने की बेफिक्री में पुनः इनके महत्त्व को ही गौण कर दिया है। अतीत में अवकाश की परिपाटी में केवल मौसम की ही गणना नहीं होती थी, अलबत्ता इस दौरान समय के सदुपयोग में शिक्षा के माहौल को प्रश्रय दिया जाता था। बेशक शिक्षा विभाग के लिए एक साथ अति सर्द, अति गर्म व अति मानसून प्रभावित क्षेत्रों के लिए अवकाश, अध्ययन और परीक्षा के लिए तिथियां तय करना इतना भी आसान नहीं है कि इनमें समरूपता लाई जाए।

वार्षिक परीक्षाओं को एक ही समय में करवाने का दबाव भी अवकाश तय करने में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन मात्र इस बहाने से योजना बनाने में दिक्कत नहीं आ सकती। कैलेंडर तो खेलों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आश्चर्य यह कि अवकाश खाके में हो रही फर्ज अदायगी आगे चलकर जिलावार आधार पर प्रशासन के सुपुर्द कर दी जाती है और छुट्टियों की मात्रा बढ़ जाती है। छुट्टियों के विपरीत खड़े अध्ययन दिवसों को सुरक्षित रखने की कहीं अधिक जरूरत है। अगर बरसात का मौसम अगस्त के आखिर और कई बार सितंबर के आरंभ तक फैल रहा है, तो जून व पंद्रह जुलाई तक के समय को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अवकाश भले ही कम हों, लेकिन इनकी बुनियाद मौसम के कुप्रभाव से बचाने का लक्ष्य निर्धारित करें। इसका एक दूसरा पहलू पढ़ाई को परीक्षा तक ले जाने का भी है और इसीलिए विभाग को अपना पढ़ाई, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों का कैलेंडर भी एकसाथ सुनिश्चित करना चाहिए। यह महज शिक्षा विभाग की लापरवाही नहीं, बल्कि शिमला से प्रदेश की नीतियां, कार्यक्रम व कार्ययोजनाएं बनाने की विडंबना भी है कि अधिकारी चंबा तक के विस्तार में सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में शिमला की सरकारी मशीनरी को पूरे प्रदेश में घुमाने की आवश्यकता जरूरी है। फैसलों की फेहरिस्त बनाने से पहले सरकार और सरकारी विभागों को प्रदेश स्तरीय दौरे व सर्वेक्षण करने चाहिएं। आज की स्थिति में कृषि व बागबानी विभाग को निजी नर्सरियों से सीखने की जरूरत है कि किस तरह मौसम के अनुरूप वैकल्पिक खेती व बागबानी में नवाचार जोड़ा जा रहा है। सरकारी बसों को चलाने का उद्देश्य और यात्री संतुष्टि को हासिल करने के लिए निजी बस संचालकों से सीखना होगा। दरअसल सरकारी महकमों को अपने लक्ष्यों में अभिप्राय देखना होगा। किसी भी सरकारी विभाग का अभिप्राय शिमला में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता तक इसका सही कार्यान्वयन है। व्यवस्था परिवर्तन को तरजीह देती सुक्खू सरकार को अपना संदेश हर विभाग के चौखट पर चस्पां करना होगा। पूर्व में भी जब वीरभद्र ने पूरे प्रदेश को लेकर सरकार का अभिप्राय दिखाना शुरू किया था, तो शिमला से कई विभागों के मुख्यालय, उनके क्षेत्रीय कार्यालय तथा निगम-बोर्डों के कार्यालय पूरे प्रदेश में स्थानांतरित कर दिए गए थे। इसी के साथ शीतकालीन प्रवास व तपोवन शीतकालीन सत्र का आगाज दरअसल सरकार के अभिप्राय को सुदृढ़ करना था।

डा. जयंतीलाल भंडारी

विदेश व्यापार बढने का परिदृश्य

यकीनन इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी देश के निर्यात और विदेश व्यापार बढने का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट में 676 अरब डॉलर मूल्य का रिकार्ड निर्यात किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत से निर्यात 767 अरब डॉलर मूल्य की ऊंचाई पर है। निःसंदेह देश निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय भारत के तेजी से बढ़ते निर्यातों का ग्राफ इस बात का प्रतीक है कि भारतीय उत्पादों की मांग दुनियाभर में बढ़ रही है। यदि हम उत्पाद निर्यात के नए आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि प्रमुख रूप से निर्यात अमेरिका, यूएई, चीन, बांग्लादेश व नीदरलैंड को भी बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए हैं। निर्यात उत्पादों के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चमड़ा, कॉफी, प्लास्टिक, रेडीमेड परिधान, मांस एवं दुग्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद और तंबाकू की निर्यात वृद्धि में अहम भूमिका रही है। साथ ही उच्च इंजीनियरिंग निर्यातों, परिधान और वस्त्र निर्यात आदि से संकेत मिलते हैं कि यह धारणा धीरे-धीरे बदल रही है कि भारत प्राथमिक जिंसों का ही बड़ा निर्यातक है। अब भारत के द्वारा अधिक से अधिक मूल्यवर्धित और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों का निर्यात भी किया जा रहा है।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत विश्व पटल पर कृषि निर्यात के नए उभरते हुए देश के रूप में उपस्थिति दर्ज करते हुए मानवता के आधार पर दुनिया के जरूरतमंद देशों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहा है। भारत से खाद्य पदार्थों अनाज, गैर बासमती चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और अन्य मोटे अनाज के अलावा फलों एवं सब्जियों के निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई है। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में खाद्य उत्पादों का निर्यात 25 अरब डॉलर था, यह वर्ष 2022-23 से 30 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में ज्यादा मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। गहराई से कृषि निर्यात परिदृश्य का अध्ययन करने के बाद कृषि निर्यात से सुधार के लिए रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि रिकॉर्ड स्तर पर दिखाई दे रहा है। वल्र्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित वैश्विक कृषि व्यापार में रुझान रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुनिया में कृषि निर्यात में भारत ने नौवां स्थान हासिल किया है। देश के कुल निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत से अधिक हो गयी। संयुक्त राष्ट्र के कृषि विभाग की रिपोर्ट को देखें तो पाते हैं कि वर्ष 2018-19 में वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 22 फीसदी थी, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 40 फीसदी हो गई। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में वैश्विक गेहूं निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.3 फीसदी थी जो वर्ष 2021-22 में पांच फीसदी तक पहुँच गई। खास बात यह है कि कोविड-19 के कारण भारत के सेवा निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं। कोविड-19 के बाद दो साल में कुल आईटी सेवाओं के निर्यात में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कोविड-19 ने अधिकांश उद्योगों को डिजिटल निवेश और मल्टी-चैनल व्यवसाय में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया और कंपनियों के बैक-एंड प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को ज्यादा बेहतर और अनुकूल बनाने के लिए प्रवृत्त किया है। आईटी सेवाओं की कुल सेवा निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसमें कंप्यूटर सेवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। फिर पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं, तकनीकी और व्यापार से संबंधित सेवाएं और अनुसंधान और विकास क्षेत्रों में भी सेवा निर्यात में प्रभावी वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि जिस तेजी से देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की संख्या बढ़ी है, उतनी ही तेजी से आईटी सेवाओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि भारत के नवाचार दुनिया में सबसे प्रतियोगी, किफायती, टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध और विकास और जबरजस्त स्टार्टअप माहौल के चलते ख्याति प्राप्त वैश्विक फार्मेसी कंपनियाँ, वैश्विक फायनेंस और कॉमर्स कंपनियाँ अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में जीसीसी स्थापित किए हैं। यह संख्या वित्त वर्ष 2015-16 में करीब 1000 से अधिक थी, वहीं यह बढक़र वित्त वर्ष 2022-23 में 1500 से अधिक हो गई है। वास्तव में भारत में लगभग 40 प्रतिशत वैश्विक जीसीसी हैं। इसमें कोई दोमत नहीं है कि पिछले वर्ष 2022 में देश से निर्यात बढ़ाने में भारत के द्वारा यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए)की भी प्रभावी भूमिका रही है।

यह भी भारत की बढ़ती हुई वैश्विक निर्यात साख की सफलता है कि रिजर्व बैंक आरबीआई ने जुलाई 2022 में डॉलर पर निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार का लेन-देन रुपये में करने का प्रस्ताव किया था। 15 मार्च तक रूस, मारीशस व श्रीलंका के द्वारा भारतीय रुपये में विदेश व्यापार शुरू करने के बाद अब तक 18 देशों के बैंकों ने रुपए में व्यापार करने के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। दुनिया के 35 से अधिक देशों ने रुपये में व्यापार करने में रुचि दिखाई है। इससे भारत को निर्यात के मोर्चे पर बड़ा लाभ मिलेगा। हमें विभिन्न उद्योगों से निर्यात बढ़ाने के वैसे ही प्रयत्न करने होंगे जैसे पिछले तीन-चार वर्षों में खिलौना उद्योग के लिए किए गए हैं। देश में खिलौना उद्योग के रणनीतिक विकास से भारत में पिछले तीन वर्षों में खिलौने के आयात में 70 फीसदी की कमी आई है। साथ ही भारत का खिलौना निर्यात करीब 300 करोड़ रुपए से तेजी से बढक़र करीब 2600 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों को खिलौने निर्यात किए जा रहे हैं।

> “ अब यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार के द्वारा एक अप्रैल 2023 से लागू की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 से निर्यात तेजी से बढ़ेंगे और वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

अब देश को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें कई बातों पर ध्यान देना होगा। भारत के द्वारा बाद अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और इजराइल के साथ एफटीए के लिए प्रगतिपूर्ण वार्ताएं तेजी से पूरी करनी होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल रुपए की जो प्रायोगिक शुरुआत हुई है, उसे अब शीघ्रता से विस्तारित करना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्युफैक्चरिंग के तहत चिन्हित 24 सेक्टर को प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जाना होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की भूमिका निर्यात बढ़ाने में अहम बनाई जानी होगी। ऐसे रणनीतिक प्रयासों और नई विदेश व्यापार नीति के उपयुक्त कार्यान्वयन से भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगा अब यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार के द्वारा एक अप्रैल 2023 से लागू की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 से निर्यात तेजी से बढ़ेंगे और वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

चिंतन विचार

भारतीय संस्कृति में छिपा जीवन का रहस्य

बाहरी कलाकारों की अपेक्षा स्थानीय कलाकारों को अधिक मौका दिया जाना चाहिए। स्थानीय कलाकारों को बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें कि प्रदेश के लोक दल दूसरे राज्यों में जाएं'

भारतीय संस्कृति समूचे विश्व को आकर्षित करती है, लेकिन हम भारतीय ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जहां हम कभी अपनी संस्कृति पर गर्व करते थे, वहीं आज का युवा वर्ग का मोह पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम पश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति केवल किताबों और कहानियों में ही कहीं गुम होती जा रही है। सबसे जरूरी है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। त्याग, सम्मान, संयम, सत्य, अहिंसा, अध्यात्म ये सभी हमारी संस्कृति की पहचान हैं। आजकल के इनसान ने अपने सिद्धान्तों और मूल्यों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। युवा वर्ग पर पश्चिमी सभ्यता का अत्यधिक प्रभाव है। युवाओं में अपनी संस्कृति और मान्यताओं से लगाव नहीं है। युवा वर्ग का गलत रास्तों पर जाना भी पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते परिणाम का ही फल है। भारतीय समाज और युवा वर्ग पर यदि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इसी प्रकार बढ़ता रहा, तो यह एक चिंतनीय विषय होगा। साथ ही पढ़ाई के प्रति उदासीनता भी बच्चों को गलत राह पर ले जाती है। युवाओं में भटकाव के पीछे एकल परिवार भी महत्त्वपूर्ण कारक है। आज दुनिया भौतिकतावादी हो गई है और लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए उनके अंदर तनाव और अवसाद बढ़ता जाता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से भी अवगत कराएं ताकि उनको सही दिशा मिल सके।

अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, घर से दूर रहकर पढ़ाई, बड़े शहरों और विदेश में नौकरी की ललक, पाश्चात्य परिवेश की ओर झुकाव और मोबाइल फोन ने युवाओं को भारतीय संस्कृति से दूर कर दिया है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अधिकतर सीरियल भी पश्चिमी संस्कृति को पोषित-पल्लवित करते हैं जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित होती है। आज का युवा तकनीकी मोहमाया से भ्रमित है। युवा वर्ग भारतीय संस्कृति की महत्ता को नहीं समझता है। इसके लिए उसके पास अनेक प्रकार के तर्क उपलब्ध होते हैं। युवा वर्ग को भारतीय संस्कृति से जोडऩे की कोशिश की जानी चाहिए। यह समय सांस्कृतिक विरासत को संभालने का समय है। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की चकाचौंध में युवा वर्ग हमारी पुरातन संस्कृति की महान विरासत को भूलते जा रहा है। नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा है, मानवता और संवेदनशीलता कम हो रही है। आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारे को तो हम भूलते ही जा रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि नैतिकता, अपनत्व और देशभक्ति जैसे मूल्यों ने ही भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में योगदान दिया है। यह जरूरी है कि हम हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। युवा वर्ग के कन्धों पर ही यह जिम्मेदारी है। आज का युवावर्ग पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर अपनी मूल भारतीय संस्कृति से विमुख होता जा रहा है जो गंभीर चिंता की बात है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर की बदौलत ही विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। इस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी युवा वर्ग की है। देश के युवा बेशक इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ें, लेकिन अपनी संस्कृति को हमेशा जिंदा रखें। भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों, धरती-जल को भी देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता है।

वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण, पोर्नसाइट के मकडज़ाल, वेब सीरीज में अश्लील दृश्यों व गंदी गालियों की भरमार ने युवा वर्ग को इस प्रकार अपने जाल में फंसाया है कि वह चाहकर भी इनसे निकल नहीं पा रहा है। युवा के मन में भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को लेकर एक आदर्श छवि बनी हुई है, लेकिन जब वह वास्तविकता के धरातल पर स्थितियों को बहुत बदला हुआ पाता है तो जाने-अनजाने में अपनी संस्कृति से दूर होता चला जाता है। अपनी महान संस्कृति से परिचित करवाने एवं युवा पीढ़ी को पथ प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। बाल्यावस्था से ही परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज न करके उन्हें समझाना चाहिए ताकि उनकी छोटी गलतियां भविष्य में अपराध का रूप न ले सकें। संदिग्ध गतिविधियों को जागरूकता और सजगता के द्वारा निरंतर हो रहे अपराधों को रोका जा सकता है। आज का युवा विदेशी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है। उसकी नजर में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का महत्त्व नहीं है।

अडानी ग्रुप के बाद TCS और Infosys पर संकट! अमेरिका के रीजनल बैंकों में है सबसे ज्यादा एक्सपोजर

पी.वी. न्यूज

अमेरिका में एक हफ्ते के भीतर दो रीजनल बैंक डूब चुके हैं। अमेरिका से शुरू हुआ यह संकट यूरोप पहुंच चुका है। यह भारत की आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है। जेपी मोर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रीजनल बैंक्स में टीसीएस और इन्फोसिस का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। बैंकिंग संकट से इन कंपनियों की परेशानी बढ़ सकती है।

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार अभी तक अडानी ग्रुप (Adani Group) के संकट से भी पूरी तरह नहीं उबर पाया है कि एक और मुसीबत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अमेरिका से शुरू बैंकिंग संकट (Banking Crisis) यूरोप पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि यह आगे और गहरा सकता है। इस बीच जेपी मोर्गन (JPMorgan) के एनालिस्ट्स का कहना है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे अमेरिका के बैंकों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर भारत की दो बड़ी आईटी कंपनियों टीसीएस (TCS) और इन्फोसिस (Infosys) का है। उनके कुल रेवेन्यू में अमेरिका के रीजनल बैंक्स की हिस्सेदारी 2-3 फीसदी है। हाल में डूब गए सिलिकॉन वैली बैंक में टीसीएस, इन्फोसिस और माइंडट्री (Mindtree) का एक्सपोजर 10 से 20 बेसिस पॉइंट हो सकता है। इसमें टाटा ग्रुप (Tata Group) की कंपनी टीसीएस का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मोर्गन ने एक नोट में कहा कि इन तीनों कंपनियों को सिलिकॉन वैली बैंक में अपने एक्सपोजर के लिए प्रॉविजन करना पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के डूबने तथा अमेरिका और यूरोप में लिक्विडिटी की चिंताओं बैंक शॉर्ट टर्म में अपने टेक बजट को कम कर सकते हैं। देश की आईटी इंडस्ट्री पहले ही यूरोप और अमेरिका में मैक्रोइकॉनमिक एनवायरमेंट की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के कारण डिमांड कम हुई है। इस कारण कंपनियां टेक्नोलॉजी पर खर्च कम कर रही हैं। बैंकिंग क्राइसिस से स्थिति और बदतर हो सकती है। इस कारण अगली कुछ तिमाहियों में आईटी कंपनियों का रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है।

किससे आता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू

भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे ज्यादा रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर से आता है। इस सेक्टर में अमेरिकी बैंकों में उनका एक्सपोजर औसतन 62 फीसदी और यूरोप में 23 फीसदी है। माइंडट्री ने हाल में कहा था कि एसवीबी समेत अमेरिकी बैंकों में उसका एक्सपोजर मामूली है।

वित्त मंत्री ने अमेरिका पहुंचकर WTO को दिखाया आईना, बोलीं- केवल सुनाएं नहीं सुनें भी

सीतारमण ने यहां शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ओर से आयोजित बातचीत के दौरान कहा, "मैं चाहूंगी कि डब्ल्यूटीओ अधिक प्रगतिशील हो, सभी देशों की बात सुने और सभी सदस्यों के प्रति निष्पक्ष रहे।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अमेरिका में विश्व व्यापार संगठन को लगभग आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत चाहता है, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और अधिक प्रगतिशील बने और सभी देशों की बात सुने, केवल सुनाए नहीं।

सीतारमण बोलीं- उन देशों की सुनी जानी चाहिए जिनके पास कहने को कुछ है

सीतारमण ने यहां शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ओर से आयोजित बातचीत के दौरान कहा, ₹मैं चाहूंगी कि डब्ल्यूटीओ अधिक प्रगतिशील हो, सभी देशों की बात सुने और सभी सदस्यों के प्रति निष्पक्ष रहे।₹ उन्होंने कहा, 'सौभाग्य से मैंने 2014 से 2017 के बीच भारत के वाणिज्य मंत्री के तौर पर डब्ल्यूटीओ के साथ कुछ समय बिताया। सीतारमण ने कहा कि उसे उन देशों की आवाज सुनने के लिए अधिक जगह देनी होगी जिनके पास सुनने के अलावे कहने के लिए भी कुछ अलग है। उन्होंने जोर दिया कि डब्ल्यूटीओ के लिए आज का संदेश अधिक खुलापन होना चाहिए।

बाजार के उदारीकरण की कीमत अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने चुकाई

उन्होने कहा कि आज अमेरिकी वाणिज्य मंत्री कैथरीन ताई के शब्दों को याद करना उपयोगी हो सकता है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि पारंपरिक व्यापार दृष्टिकोण क्या है? वास्तव में बाजार को उदार बनाना क्या है? शुल्क में कमी के संदर्भ में वास्तव में इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, 'अब ये सवाल ग्लोबल साउथ के कई देशों के मन में है। यह एक ऐसा समय है जब विभिन्न देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आप किस हद तक बाजार का उदारीकरण चाहते हैं? अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने इसकी कीमत चुकाई है, अमेरिकी वाणिज्य सचिव की चिंता उसी से संबंधित है। वर्ष 2014 और 2015 के दौरान वाणिज्य मंत्री के तौर पर मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। शायद मेरी अभिव्यक्ति को वैश्विक मीडिया में कभी जगह नहीं मिली, पर अब ग्लोबल साउथ के कई देशों की भी यही भावना है।'

भारत में हम कोटा मुक्त, टैरिफ मुक्त व्यापार प्रणाली अमल में लाए रहे: वित्त मंत्री

उन्होंने कहा कि अब भारत में कोटा मुक्त, टैरिफ मुक्त व्यापार प्रणाली को अमल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इसलिए कोई भी देश, चाहे वह अफ्रीका का हो या प्रशांत क्षेत्र का, आकांक्षी हो या कम आया वाला देश हो भारत में निर्यात कर सकते हैं। हम जहां तक संभव हो सके बाजार को खोल रहे हैं।

वित्त मंत्री बोलीं- भारत का ध्यान कौशल विकास और डिजिटलीकरण पर

भारत का ध्यान कौशल और डिजिटलीकरण पर होने जा रहा है ताकि जीवन यापन, पारदर्शिता और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में अधिक आसानी हो। सीतारमण ने सोमवार को पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक थिंक टैंक में एक बातचीत में कहा कि सरकार का दृष्टिकोण गरीब लोगों को कम से कम बुनियादी सुविधाओं के साथ सशक्त बनाना है।

इनसाइड

'महंगाई का सबसे बुरा दौर गुजर चुका', अमेरिका के बैंकिंग संकट पर ये बोले गवर्नर शक्तिकांत दास

नई दिल्ली। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हमारा विदेशी कर्ज मैनेजेबल (नियंत्रण में) है, इसलिए डॉलर के मजबूत होने से हमें कोई समस्या नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकिंग प्रणाली के लिए अत्यधिक जमा या ऋण वृद्धि खराब है। उन्होंने कहा विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट का जोखिम समाप्त हो गया है। दास ने कहा, ₹हमारा वित्तीय क्षेत्र स्थिर है और हमने महंगाई के सबसे बुरा दौर को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हमारा विदेशी कर्ज मैनेजेबल (नियंत्रण में) है, इसलिए डॉलर के मजबूत होने से हमें कोई समस्या नहीं है। RBI गवर्नर ने डॉलर में वृद्धि के कारण उच्च विदेशी ऋण जोखिम वाले देशों की मदद के लिए G20 देशों की ओर से समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जी-20 देशों को युद्ध स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित देशों को जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण प्रदान करना चाहिए। दास के अनुसार अमेरिका में जारी बैंकिंग संकट मजबूत नियामकों और सतत वृद्धि के महत्व को बढ़ाता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा अमेरिकी बैंकिंग संकट स्पष्ट रूप से वित्तीय प्रणाली के लिए निजी क्रिप्टोकरेंसी के जोखिम को दर्शाता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17वें के पी होर्मिस स्मारक व्याख्यान में कहा कि अमेरिकी बैंकों का संकट विवेकपूर्ण परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन की जरूरत को दर्शाता है। दास ने सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का जिक्र करते हुए कहा कि बैंकों को बांड में निवेश करने से पहले उचित जोखिम आकलन करना चाहिए।

कहीं काम के दबाव में ऑफिस में सो रहे लोग, ये कंपनी सोने की दे रही छुट्टी, वो भी भारत में

नई दिल्ली: ऑफिस में कर्मचारियों को कई तरह की छुट्टी दी जाती हैं। इसमें सिक लीव, ईएल और सीएल शामिल होती हैं। लेकिन कई बार ऑफिसों में काम के दबाव के बीच लोगों को छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें ट्विटर (Twitter) की एक कर्मचारी ऑफिस में बिस्तर लगाकर सोते हुए दिख रही थी। लेकिन अगर किसी ऑफिस में आपको सोने के लिए भी छुट्टी दी जाए तो आप क्या कहेंगे। एक कंपनी अपने कर्मचारियों को सोने के लिए छुट्टी दी है। ये कोई विदेशी कंपनी नहीं बल्कि भारत की कंपनी है। आज वर्ल्ड स्लीप डे (World Sleep Day 2023) पर बेंगलुरु की कंपनी ने अपने कर्मचारियों को यह अनोखा गिफ्ट दिया है। बेंगलुरु की एक फर्म ने अपने कर्मियों को अनोखा गिफ्ट दिया है। कंपनी ने इंटरनेशनल स्लीप डे (World Sleep Day 2023) पर सभी को छुट्टी दे दी है ताकि वे सो सकें। कंपनी ने कहा कि उसे यह घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि शुक्रवार 17 मार्च 2023 को अंतराष्ट्रीय नींद दिवस के मौके पर वैकल्पिक छुट्टी दी गई है।

आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया, जानें क्या बदलाव हुआ

आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1 प्रतिशत से घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1 प्रतिशत से घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

आईएमएफ ने अपने वार्षिक विश्व आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए पूर्वानुमान को इस साल जनवरी के 6.8 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 5.9 प्रतिशत रही जो उससे पिछले वर्ष 6.8 प्रतिशत थी।

जीडीपी पर आईएमएफ के ताजा अनुमान रिजर्व बैंक के अनुमानों से कम

भारत की वृद्धि दर के संबंध में आईएमएफ के ताजा अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक अनुमानों से कम हैं। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर सात प्रतिशत रहेगी जबकि एक अप्रैल से शुरू हुए चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बता दें कि सरकार ने अभी तक 2022-23 के लिए पूरे साल के जीडीपी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। विश्व आर्थिक परिदृश्य के आंकड़ों से पता चलता है कि विकास दर के अनुमान 2022 के 6.8 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 5.9 प्रतिशत होने के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

ग्लोबल चुनौतियों से धीरे-धीरे उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था

चीन की वृद्धि दर 2023 में 5.2 प्रतिशत और 2024 में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2022 में इसकी वृद्धि दर तीन प्रतिशत थी। ऊपरी तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी के शक्तिशाली झटकों और रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रही है।

कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम टैक्स सेविंग ? जानिए, एक्सपर्ट की राय

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार अभी तक अडानी ग्रुप (Adani Group) के संकट से भी पूरी तरह नहीं उबर पाया है कि एक और मुसीबत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अमेरिका से शुरू बैंकिंग संकट (Banking Crisis) यूरोप पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि यह आगे और गहरा सकता है। इस बीच जेपी मोर्गन (JPMorgan) के एनालिस्ट्स का कहना है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे अमेरिका के बैंकों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर भारत की दो बड़ी आईटी कंपनियों टीसीएस (TCS) और इन्फोसिस (Infosys) का है। उनके कुल रेवेन्यू में अमेरिका के रीजनल बैंक्स की हिस्सेदारी 2-3 फीसदी है। हाल में डूब गए सिलिकॉन वैली बैंक में टीसीएस, इन्फोसिस और माइंडट्री (Mindtree) का एक्सपोजर 10 से 20 बेसिस पॉइंट हो सकता है। इसमें टाटा ग्रुप (Tata Group) की कंपनी टीसीएस का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मोर्गन ने एक नोट में कहा कि इन तीनों कंपनियों को सिलिकॉन वैली बैंक में अपने एक्सपोजर के लिए प्रॉविजन करना पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के डूबने तथा अमेरिका और यूरोप में लिक्विडिटी की चिंताओं बैंक शॉर्ट टर्म में अपने टेक बजट को कम कर सकते हैं। देश की आईटी इंडस्ट्री पहले ही यूरोप और अमेरिका में मैक्रोइकॉनमिक एनवायरमेंट की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के कारण डिमांड कम हुई है। इस कारण कंपनियां टेक्नोलॉजी पर खर्च कम कर रही हैं। बैंकिंग क्राइसिस से स्थिति और बदतर हो सकती है। इस कारण अगली कुछ तिमाहियों में आईटी कंपनियों का रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है।

किससे आता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू

भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे ज्यादा रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर से आता है। इस सेक्टर में अमेरिकी बैंकों में उनका एक्सपोजर औसतन 62 फीसदी और यूरोप में 23 फीसदी है। माइंडट्री ने हाल में कहा था कि एसवीबी समेत अमेरिकी बैंकों में उसका एक्सपोजर मामूली है। टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और मार्केट कैप के हिसाब से मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टीसीएस का शेयर शुक्रवार को 0.18 फीसदी गिरावट के साथ 3178.95 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी ओर इन्फोसिस का शेयर 10.4 फीसदी की तेजी के साथ 1420.85 रुपये पर पहुंच गया।

गेहूं खरीद के मापदंडों में सरकार ने दी ढील; पंजाब, हरियाणा, चंढ़ीगढ़ व राजस्थान के किसानों को होगा लाभ

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा, 'फील्ड सर्वे के बाद हमने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है ताकि किसानों की कठिनाई को कम किया जा सके और गेहूं की बिक्री में परेशानी से बचा जा सके।

नई दिल्ली। केंद्र ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है ताकि संकटग्रस्त बिक्री को रोका जा सके और साथ ही किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने इन राज्यों के कुछ हिस्सों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन राज्य सरकारों ने खरीद मानदंडों में ढील देने की मांग की थी। वर्तमान में, मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद चल रही है, जबकि अन्य राज्यों में असामयिक बारिश के कारण इसमें देरी हुई है। राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर गेहूं की खरीद करती है।

फील्ड सर्वे के बाद सरकार ने लिया फैसला

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा, 'फील्ड सर्वे के बाद हमने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है ताकि किसानों की कठिनाई को कम किया जा सके और गेहूं की बिक्री में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने समान विनिर्देशों के तहत 6 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के मुकाबले सिकुड़े हुए और टूटे हुए अनाज की सीमा में 18 प्रतिशत तक की ढील दी है।

उन्होंने कहा कि छह प्रतिशत तक सिकुड़े और टूटे हुए अनाज वाले गेहूं के मूल्य में कोई कटौती लागू नहीं होगी। मूल्य कटौती 10 प्रतिशत तक चमक हानि वाले गेहूं पर लागू नहीं होगी, जबकि 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चमक हानि वाले गेहूं पर फ्लैट आधार पर 5 रुपये 31 पैसे प्रति क्विंटल की दर से मूल्य कटौती की जाएगी। इसके अलावे क्षतिग्रस्त और हल्के क्षतिग्रस्त अनाज की मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने चालू विपणन वर्ष में 10 अप्रैल तक 13.20 लाख टन गेहूं की खरीदारी की है

सिंह ने आगे कहा कि भंडारण के दौरान नियमों में ढील के तहत खरीदे गए गेहूं के स्टॉक की गुणवत्ता में किसी भी तरह की गिरावट पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इस गेहूं का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के 10 अप्रैल तक 13.20 लाख टन गेहूं खरीदा है, जिसमें ज्यादातर मध्य प्रदेश से हैं। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में पंजाब में लगभग 1,000 टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि हरियाणा में 88,000 टन गेहूं खरीदा गया है। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 34.2 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष हुई 19 मिलियन टन गेहूं खरीद के मुकाबले अधिक है। पिछले साल लू और बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में मामूली गिरावट के कारण गेहूं की खरीद में गिरावट आई थी। हालांकि, इस साल उत्पादन रिकॉर्ड 112.2 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

प्यार में दिल टूटा तो आशिक को मिले 25000, जानिए क्या है हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस फंड

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर प्रतीक आर्यन नाम के एक ट्विटर यूजर का एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। प्रतीक ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने पोस्ट में लिखा है कि उसने और उसकी गर्ल फ्रेंड ने अपनी प्रेम कहानी शुरू करने के दौरान तय किया था कि वे दोनों हर महीने एक ज्वॉइंट अकाउंट में 500 रुपये जमा करेंगे और जो धोखा खाएगा उसे पूरी राशि दे दी जाएगी। प्यार में दिल टूटने पर अक्सर लोग हताश और निराश हो जाते हैं। कुछ लोग इससे उबरने में सफल हो जाते हैं पर कुछ लोगों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए ये खबर उम्मीद की एक किरण साबित हो सकती है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर वर्यित हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस फंड के बारे में, जो प्यार में धोखा खाकर टूट चुके लोगों को दोबारा आत्मविश्वास हासिल करने में बड़ी मदद कर सकता है। सोशल मीडिया पर प्रतीक आर्यन नाम के एक ट्विटर यूजर का एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। प्रतीक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने पोस्ट में लिखा है कि उसने और उसकी गर्ल फ्रेंड ने अपनी प्रेम कहानी शुरू करने के दौरान तय किया था कि वे दोनों हर महीने एक ज्वॉइंट अकाउंट में 500 रुपये जमा करेंगे। दोनों ने यह समझौता किया था कि जो भी धोखा खाएगा, उसे ये पूरी राशि हार्टब्रेक इंश्योरेंस फंड के रूप में दे दी जाएगी। बाद में प्रतीक ने इस मद में 25 हजार रुपये मिलने की बात कही है। मतलब उनका ब्रेकअप हो गया है और उन्हें हार्टब्रेक इंश्योरेंस फंड के रूप में 25 हजार रुपये मिल गए हैं।

सेवानिवृत्ति की अवधि तक सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि के हकदार, KPTCL की याचिका पर सुप्रीम फैसला

शीर्ष अदालत ने मंगलवार को यह फैसला राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की अपील पर सुनाया। केपीटीसीएल ने कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को चुनौती दी थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित एक मामले में अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं, जो उस अवधि तक रिटायर ना हुए हों। पीठ ने कहा कि ऐसे सभी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए भले ही वे यह लाभ पाने के एक दिन बाद ही सेवानिवृत्त क्यों न हो जाएं।

शीर्ष अदालत ने मंगलवार को यह फैसला राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की अपील पर सुनाया। केपीटीसीएल ने कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार थे, भले ही वे उसके अगले ही दिन रिटायर हो गए हों।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने सुनवाई करते हुए केपीटीसीएल की इस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता (केपीटीसीएल) की ओर से यह दलील दी गई है कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे में जबकि कोई कर्मचारी सेवा में नहीं रहता है तो उसे उसे वार्षिक वेतन वृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

अच्छे आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा वेतनवृद्धि का आधार

सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने इस मामले से जुड़े विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों और संबंधित कानूनों पर गौर करने और वार्षिक वेतन वृद्धि के लक्ष्य और उद्देश्य का विश्लेषण करने के बाद अपना फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वृद्धि प्रदान की जाती है, बशर्ते उसे दंड के रूप में रोका न गया हो या उसे दक्षता के साथ जोड़ा न गया है। इसलिए, वेतन वृद्धि एक वर्ष या निश्चित अवधि के दौरान अच्छे आचरण के साथ सेवा प्रदान करने के लिए अर्जित की जाती है।

वेतन वृद्धि प्रदान की गई सेवा के लिए

पीठ ने आगे कहा, वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ की पात्रता पहले से प्रदान की गई सेवा के कारण है। सिर्फ इसलिए की कोई कर्मचारी अगले दिन सेवानिवृत्त होने वाला है, उसे वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता जिसे उसने गुजरते साल के दौरान अच्छी सेवा के लिए अर्जित किया है। इसको देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति के दिन कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का उचित फैसला दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकारी कंपनी के हक में फैसला दिया था।

चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ जापान, कहा- मुकाबले की तैयारी करें

हडसन इंस्टीट्यूट के फैलो सटोरू नागाओ ने कहा कि पड़ोसियों के साथ बीजिंग का लगातार सीमा विवाद काफी खतरनाक है। चीन सोचता है कि यह उनका क्षेत्र है, इसलिए उसे नाम बदलने का अधिकार है। इससे समझ आता है कि चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है। यह बहुत खतरनाक है।

नई दिल्ली। एक जपानी फैलो ने कहा कि चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है। उन्होंने कहा कि भारत को चीन के क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्वान ने जिक्र किया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर भी दावा किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है।

विस्तारवादी नीति अपनाता है चीन

हडसन इंस्टीट्यूट के फैलो सटोरू नागाओ ने कहा कि पड़ोसियों के साथ बीजिंग का लगातार सीमा विवाद काफी खतरनाक है। चीन सोचता है कि यह उनका क्षेत्र है, इसलिए उसे नाम बदलने का अधिकार है। इससे समझ आता है कि चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है। यह बहुत खतरनाक है। भारत की तरह चीन ने जापान के इलाके पर भी दावा किया है। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जापानी फैलो ने कहा कि जिस द्वीप को हम सेनकाकू कहते हैं, उसे चीन दियाओयू द्वीप कहता है। चीन को लगता है कि उसे नाम बदलने का अधिकार है।

सैन्य प्रदर्शन भी करता है चीन

फैलो ने आगे कहा कि बीजिंग पड़ोसियों के खिलाफ ना केवल सैन्य कौशल का उपयोग कर रहा है बल्कि दूसरों के क्षेत्रों का शोषण भी कर रहा है। वह वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में पैसे लगाकर अपनी योजना पूरी कर रहा है। सटोरू नागाओ ने कहा कि चीन के लिए तटीय शहर सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए चीन इन मार्गों को सुरक्षित करना चाहता है।

पाकिस्तान तक पहुंच की कोशिश

विद्वान ने चीन के विस्तारवादी लक्ष्यों के लिए अमेरिकी नौसेना अपना प्रभाव दिखाती है। भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार क्षेत्र में तैनात है। यदि चीन इस मार्ग में आया तो उसे नुकसान होगा। इसलिए वह रूट डायवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चीन पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग बना रहा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और झिंजियांग से होकर गुजर रहा है। जापानी फैलो ने कहा कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर वास्तव में भारत का क्षेत्र है। चीनी रोड के कारण भारत के दावे का उल्लंघन होगा। इसलिए भारत को चीन के लिए तैयार रहना होगा।

टीएमसी नेता फलेरियो ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा; गोवा में नहीं लड़े थे चुनाव, खफा था पार्टी नेतृत्व

फलेरियो ने 2022 विधानसभा चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई के खिलाफ फतोर्दा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस वजह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फलेरियो से खफा चल रहा था।

नई दिल्ली। टीएमसी राज्यसभा सांसद और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा ने लुइजिन्हो के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से गोवा में पार्टी के मामलों से दूर रहने के कारण फलेरियो से टीएमसी पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा मांगा जा रहा था।

फलेरियो ने कहा कि वह खुद को इस जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहते हैं ताकि गोवा के हित में फिर से एक सिपाही के रूप में काम कर सकें। वह जल्द ही टीएमसी से भी इस्तीफा दे देंगे। फलेरियो सितंबर 2021 में टीएमसी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने उनसे संपर्क किया है। हालांकि इस समय मैं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैंने राज्यसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है।

मामले में टीएमसी के एक नेता ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पार्टी इस सीट के लिए नए उम्मीदवार की घोषणा करेगी। फलेरियो को लंबे समय से गोवा में पार्टी के मामलों से दूर रखा जा रहा था और उन्हें टीएमसी नेतृत्व द्वारा राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा था। टीएमसी सूत्रों ने कहा कि उन्हें कुछ महीने पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ समय मांगा था।

फलेरियो ने अपने दो पन्नों के त्यागपत्र में कहा कि उन्होंने गोवा का निवासी सांसद होने लेकिन गोवा से सांसद नहीं होने की चुनौती और निराशा का सामना किया। जब मैंने सांसद विकास निधि (एमपीलैड) कोटा से धन हासिल करने का प्रयास किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आवंटित धन का केवल 25,00,000 रुपये उस राज्य (पश्चिम बंगाल) के बाहर खर्च कर सकता हूं, जहां से मैं चुना गया हूं।

फलेरियो ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय फ्रांसिस्को लुइस गोम्स के नाम पर एक स्मारक बनाने के अपने प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं थोड़ा और जुटा सकता, लेकिन वह भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी और गोवा के एक व्यक्ति को सम्मान देने के मेरे सपने के लिए पर्याप्त नहीं होता। फलेरियो ने कहा कि पार्टी को आवंटित सीमित समय के कारण गोवा से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए राज्यसभा में अधिक समय नहीं होता था, जिससे वह गोवा के मुद्दों को उस तरह से नहीं उठा पाते थे, जिस तरह से एक प्रभाव के लिए उठाना जरूरी था।

यह है पूरा मामला

टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक, फलेरियो ने 2022 विधानसभा चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई के खिलाफ फतोर्दा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था।

नफरती भाषण मामला: काजल हिंदुस्तानी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित, 13 अप्रैल को सुनाया जाएगा फैसला

अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम गोहेल ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएम असोदिया की कोर्ट ने काजल की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है।

नई दिल्ली। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता काजल हिन्दुस्तानी की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। काजल पर रामनवमी के मौके पर कथित रूप से नफरती और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। काजल के भाषण के चलते ऊना शहर में सांप्रदायिक झड़प हुई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहम गोहेल ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएम असोदिया की कोर्ट ने काजल की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले दक्षिणपंथी नेता काजल हिंदुस्तानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। काजल हिंदुस्तानी ने बीते रविवार को ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद काजल हिंदुस्तानी को उना की अदालत के सामने पेश किया गया था। आरोप है कि काजल हिंदुस्तानी ने 30 मार्च को राम नवमी के अवसर पर भड़काऊ भाषण दिया। जिसके चलते एक अप्रैल की रात उना में दंगे हुए। पुलिस ने दो अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज की और काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

अपने ट्विटर बायो में काजल हिंदुस्तानी खुद को एंटरप्रेन्योर, रिसर्च एनालिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी बताती हैं। साथ ही वह खुद को गर्व से भारतीय भी बताती हैं। ट्विटर पर काजल हिंदुस्तानी के 92 हजार फॉलोअर्स हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में भी काजल हिंदुस्तानी शामिल होती रहती हैं। अपने भड़काऊ बयानों के चलते वह अक्सर चर्चा में रहती हैं।

बता दें कि उना दो दिनों तक सांप्रदायिक तनाव से धधकता रहा था। इस दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प और पथराव की घटनाएं हुईं थी। पुलिस ने उना हिंसा मामले में 76 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 323, 337, 143, 147 और 148 के तहत केस दर्ज किया गया था। उना हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 96 लोगों को गिरफ्तार किया है।

CM एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, पूछा- जब विवादित ढांचा गिराया गया, तब कहां थे?

परिवहन विशेष न्यूज

एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर उन लोगों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने पूछा कि जब ढांचा गिराया गया तो पाटिल का मतलब पूर्व मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) के ठिकाने के बारे में जानना था।

मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्य के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल की उस टिप्पणी को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था।

शिंदे ने किसी का नाम लिए बगैर वीडी सावरकर का 'अपमान' किए जाने पर चुप रहने के लिए उद्धव और उनके नेतृत्व वाले धड़े की आलोचना की। उन्होंने उद्धव पर उन लोगों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब ढांचा गिराया गया तो पाटिल का मतलब पूर्व मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) के ठिकाने के बारे में जानना था।

जब मस्जिद गिराई गई, तब कहा थे पूर्व मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे

उन्होंने आगे कहा, ₹मैंने चंद्रकांत पाटिल से बात की। उनके कहने का मतलब था कि जब मस्जिद गिराई जा रही थी तब पूर्व मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) और अब जो बोल रहे हैं (राज्यसभा सदस्य संजय राउत) कहां थे।₹ उन्होंने कहा कि शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे ने 'गर्व के साथ कहो हम हिंदू हैं' का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, ₹बाबरी मामले में बालासाहेब लखनऊ की अदालत में गए थे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल और उमा भारती भी थे। वहां (अयोध्या में उस स्थल पर जहां कभी ढांचा हुआ करता था) कोई पार्टी नहीं थी, सभी भगवान राम के भक्त थे।

हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवाद है, भाजपा बताए उसका हिंदुत्व क्या: उद्धव ठाकरे

इससे पहले दिन में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिंदे को या तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या बाबरी विध्वंस संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर पाटिल का इस्तीफा मांगना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व 'राष्ट्रवाद' है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बताना चाहिए कि उसका हिंदुत्व क्या है। शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटक दल हैं।

अगर बालासाहेब नहीं होते तो क्या होता?

शिंदे ने कहा कि जब मुंबई में (बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद) सांप्रदायिक दंगे भड़के तो बाल ठाकरे ने ही शहर की रक्षा की। उन्होंने कहा, ₹अगर बालासाहेब नहीं होते तो क्या होता? बालासाहेब ने जब भी देश या राज्य को किसी संकट का सामना करना पड़ा, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया।₹ उद्धव पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि बालासाहेब ने जरूरत पड़ने पर सावरकर, हिंदुत्व और राष्ट्रीय हित सहित कई मुद्दों पर साहसिक रुख अपनाया।

उन्होंने कहा, ₹जो लोग अब बात कर रहे हैं, उन्हें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सावरकर का अपमान होने पर वे चुप रहे। वे सावरकर का अपमान करने वालों के साथ खड़े हैं। वे उन लोगों को गले लगा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था।₹ शिंदे ने दोहराया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने बाल ठाकरे के सपने को पूरा किया जो अयोध्या में राम मंदिर चाहते थे और अनुच्छेद 370 हटाना चाहते थे।

ओलावृष्टि के प्रभावित किसानों को मदद का आश्वासन

उन्होंने एक गांव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण किया और प्रभावित किसानों को मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, ₹मैंने राज्य के मुख्य सचिव और संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि जब मैं अयोध्या में था तो फसलों के नुकसान का पंचनामा तुरंत करें।₹ शिंदे ने कहा कि फसलों के नुकसान का पंचनामा या नुकसान का आकलन युद्धस्तर पर किया जाएगा और किसानों को सरकार से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एनडीआरएफ के मौजूदा मानदंडों से परे मदद देने का फैसला कर चुकी है।

किसानों के मुद्दों का न हो राजनीतिकरण

बारिश से प्रभावित किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने और अयोध्या जाने को लेकर विपक्ष की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह मेरी सरकार है जिसने पूर्ववर्ती एमवीए सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने केवल घोषणाएं कीं, लेकिन क्या उन्होंने किसानों को पैसा दिया? लेकिन हमने पैसा दिया। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय योजना की तर्ज पर 'नमो सम्मान शेतकारी योजना' लेकर आई है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, ₹जब मैं अयोध्या गया था, तो मैंने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि किसान आपदाओं से सुरक्षित रहें। मैंने प्रार्थना की कि किसानों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बचाया जाए।₹ उन्होंने कहा कि अयोध्या से आने के बाद वह एक नई प्रेरणा से भर गए हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023